



04 - अखिर कैसे आए ये चुनाव परिणाम



05 - समरसता, मक्ति और सामाजिक चेतना के आद्य प्रवर्तक

A Daily News Magazine

इंदौर

गुरुवार, 07 मई, 2026



इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 11 अंक 213, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रु. 2



06 - लीज प्रकरण मामले में एसडीएम ने न्यायालयीन सीट से उठकर पहुंची...



07 - नियंत्रित पादरक्षिता की ओर बढ़ता भारत

# कैद

subhasaverenews@gmail.com  
facebook.com/subhasaverenews  
www.subhasavere.news  
twitter.com/subhasaverenews

## शहर की सुबह

चौद पर बस्ती बसाना तो चौद का कोयला मत निकालना  
रोकना मत चौद की नदियाँ  
चौद पर बस्ती बसाना तो घरों पर सोलर सिस्टम नहीं  
अर्थ सिस्टम लगाना ताकि थोड़ा बहुत कम हो धरती का ताप  
चौद पर बस्ती बसाने वालों धरती को तो रहने नहीं दिया  
पर चौद को रहने देना  
चौद  
इसलिए कि जब कभी आओ धरती पर तो तुम्हें चौद दिखे चौद जैसा।  
-वसंत सकरगाए

## प्रसंगवश

# बंगाल के मुसलमान चुनाव में ममता से कैसे दूर हो गए

मौसमी दासगुप्ता

मुर्शिदाबाद, मालदा और नॉर्थ दिनाजपुर में हिंदू वोट BJP के पक्ष में एकजुट हो गए, लेकिन मुस्लिम वोट अलग-अलग पार्टियों में बंट गए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की बड़ी जीत के पीछे मुस्लिम बहुल सीटों में बढ़त एक बड़ा कारण रही। खासकर मुर्शिदाबाद, मालदा और नॉर्थ दिनाजपुर जिलों में हिंदू वोट एकजुट हो गए और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का मुस्लिम वोट बैंक बंट गया। यह सब वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (SIR) के बीच हुआ। इस चुनाव में मुस्लिम वोट कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) और कुछ हद तक हुमायूँ कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) में बंटते दिखे। इन तीनों जिलों में अल्पसंख्यक आबादी 50 प्रतिशत या उससे ज्यादा है। बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 43 सीटें मुर्शिदाबाद, मालदा और नॉर्थ दिनाजपुर में हैं। बीजेपी, जिसने 2021 में इन 43 सीटों में सिर्फ 8 जीती थीं, इस बार 19 सीटें जीत गईं—यानी 11 सीटों का फायदा। वहीं टीएमसी, जो 2021 में 35 सीटें जीती थी, इस बार घटकर 22 पर आ गई। इसके अलावा मुर्शिदाबाद में कांग्रेस और AJUP ने 2-2 सीटें जीतीं, जबकि सीपीआई(एम) को 1 सीट मिली। कई राजनीतिक विश्लेषकों के अनुमान के उलट,

SIR के दौरान करीब 91 लाख वोटर हटाए जाने के बावजूद मुस्लिम वोट टीएमसी के पीछे एकजुट नहीं हुए। बल्कि ये वोट ज्यादातर कांग्रेस और सीपीआई(एम) में बंट गए। चुनाव आयोग के डेटा के विश्लेषण से यह बात सामने आई। कुछ सीटों पर हुमायूँ कबीर की AJUP ने भी टीएमसी के मुस्लिम वोट में सेंध लगाई। वहीं इन जिलों की हिंदू बहुल सीटों पर हिंदू वोट बीजेपी के पक्ष में एकजुट हो गए। उदाहरण के लिए, मुर्शिदाबाद के रानीनगर सीट पर कांग्रेस ने 79,423 वोट लेकर जीत हासिल की। टीएमसी 76,722 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रही और सीपीआई(एम) 48,587 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रही। इससे साफ दिखता है कि मुस्लिम वोट बंट गए। 2021 में यह सीट टीएमसी ने जीती थी। नवगाम सीट—जो मुर्शिदाबाद में हिंदू बहुल है—वहाँ बीजेपी ने 78,739 वोट लेकर जीत दर्ज की। टीएमसी 72,820 वोट के साथ दूसरे और कांग्रेस 50,144 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रही। 2021 में यहाँ टीएमसी जीती थी। मुर्शिदाबाद की खरग्राम सीट पर बीजेपी की मिताली माल ने 77,748 वोट लेकर जीत हासिल की। टीएमसी को 68,415 वोट मिले और सीपीआई(एम) 41,944 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रही। मुर्शिदाबाद की कांटी सीट, जहाँ 76 प्रतिशत आबादी हिंदू है, वहाँ बीजेपी ने 73,355 वोट से जीत हासिल की। टीएमसी को 63,020 वोट मिले और कांग्रेस

31,160 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रही। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM को 22,976 वोट मिले। मालदा और नॉर्थ दिनाजपुर में भी ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिला—हिंदू वोट बीजेपी के पक्ष में एकजुट हुए और मुस्लिम वोट बंट गए, जिससे बीजेपी को इन 43 सीटों पर बड़ा फायदा हुआ। 2011 की जनगणना के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में 2.4 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं, जो राज्य की 9 करोड़ आबादी का करीब 27 प्रतिशत हैं। 2011 में लेफ्ट सरकार के 34 साल के शासन के बाद से यह समुदाय बड़े पैमाने पर टीएमसी को वोट देता रहा है। 2021 के चुनाव में एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध के कारण तेज धुवीकरण हुआ था और मुसलमानों ने बड़ी संख्या में टीएमसी को वोट दिया था। उस चुनाव में पार्टी ने इन तीन जिलों की 43 में से 35 सीटें जीती थीं। मुस्लिम आबादी वाले जिलों का प्रदर्शन: चुनाव आयोग के अनुसार, मुर्शिदाबाद जिले की 22 सीटों में से बीजेपी ने 9 सीटें जीतीं, जबकि 2021 में उसने सिर्फ 2 सीटें जीती थीं। 2011 की जनगणना के मुताबिक, मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी 66.3 प्रतिशत है। 2021 में टीएमसी ने यहाँ 20 सीटें जीती थीं, लेकिन इस बार यह घटकर 9 रह गई। SIR के दौरान जिले में करीब 4.55 लाख वोटर हटाए गए—औसतन हर सीट से 20,668 वोटर कम

हूए। इन हटाए गए वोटों का असर टीएमसी के कुल वोट पर पड़ा और उसे नुकसान हुआ। मालदा में, जहाँ 39 लाख की आबादी में 51.3 प्रतिशत मुसलमान हैं—बीजेपी ने 12 में से 6 सीटें जीतीं, जबकि टीएमसी ने 8 सीटें जीतीं। 2021 में टीएमसी ने 8 और बीजेपी ने 4 सीटें जीती थीं। मालदा में SIR के दौरान 2.39 लाख नाम हटाए गए। यानी हर सीट से औसतन 19,948 वोटर हटे। उत्तरी दिनाजपुर में, जहाँ मुस्लिम आबादी 49.9 प्रतिशत है—9 में से 4 सीटें बीजेपी को मिलीं और टीएमसी ने 5 सीटें जीतीं। 2021 में टीएमसी ने 7 और BJP ने 2 सीटें जीती थीं। उत्तरी दिनाजपुर में 1.76 लाख वोटर लिस्ट से हटाए गए। इसके अलावा साउथ 24 परगना और बीरभूम में भी बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ। 2011 की जनगणना के अनुसार इन जिलों में करीब 35 प्रतिशत आबादी मुस्लिम है। 2021 में टीएमसी ने इन दोनों जिलों में 40 सीटें जीती थीं, जबकि बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। इस बार आंकड़े बीजेपी के पक्ष में काफी बदल गए हैं। साउथ 24 परगना की भांगर सीट पर बीजेपी और टीएमसी के अलावा, ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंट के एमडी नवसाद सिद्दीकी ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की। इन पांच जिलों में मिलाकर राज्य की 85 सीटें आती हैं। (दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

# सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा को आज हरी झंडी दिखाएंगे सीएम

● मध्यप्रदेश से पहली बार जा रहा 1100 श्रद्धालुओं का दल



भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार, 7 मई को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से 'सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा' के प्रथम जलथे को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित यह गौरवशाली यात्रा 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' के अंतर्गत निकाली जा रही है। भारत की सांस्कृतिक चेतना, आस्था और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व-2026 (8 से 11 जनवरी 2026) का शुभारंभ ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर से किया गया

है। मध्यप्रदेश से पहली बार निकलने वाली इस विशेष यात्रा में प्रदेश के विभिन्न अंचलों से 1,100 श्रद्धालुओं का दल सम्मिलित होगा। यह रेलगाड़ी भोपाल और उज्जैन रेलवे स्टेशनों से भी तीर्थयात्रियों को अपने साथ लेकर सोमनाथ की ओर प्रस्थान करेगी। यात्रा के दौरान श्रद्धालु सोमनाथ की पावन धरा पर आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, दर्शन और आध्यात्मिक अनुष्ठानों में सहभागिता करेंगे। संचालक संस्कृति श्री एन.पी. नामदेव ने बताया कि 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' का

उद्देश्य देशभर के राज्यों के माध्यम से भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान, हजार वर्षों के संघर्ष और आस्था का स्मरण करना है। यह उत्सव राष्ट्र की गौरवमयी विरासत के उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। यह पर्व केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना के पुनरुत्थान और राष्ट्रीय अस्मिता का महाकुंभ है। इसका उद्देश्य देशवासियों को उन हजार वर्षों के लंबे संघर्ष और आस्था की याद दिलाना है, जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय सांस्कृतिक ज्योति को बुझने नहीं दिया। सोमनाथ मंदिर, जो हमारे राष्ट्रीय गौरव और अडिग श्रद्धा का प्रतीक है, वहीं से इस पावन पर्व की प्रेरणा ली गई है जिससे भावी पीढ़ी अपनी विरासत पर गर्व कर सके। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में निकाली जा रही यह यात्रा प्रदेश की सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय भावना को और अधिक सशक्त करेगी। श्रद्धा और भक्ति के इस अनूठे संगम का समापन 11 मई, 2026 को होगा, जब यह दल सोमनाथ महादेव का आशीर्वाद और सांस्कृतिक गौरव की स्मृतियाँ लेकर वापस लौटेगा। यह यात्रा जन-जन के मन में स्वाभिमान और श्रद्धा का नया संचार करेगी।



# एमपी में कांग्रेस आज करेगी आगरा-मुम्बई हाईवे जाम

किसानों की समस्याओं को लेकर 7 जगह प्रदर्शन करेंगे कांग्रेसी

भोपाल। मप्र में आज गुरुवार 7 मई को कांग्रेस बड़े आंदोलन की तैयारी में है। पार्टी प्रदेशभर में 7 अलग-अलग स्थानों पर नेशनल हाईवे जाम करेगी। आंदोलन का नेतृत्व वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने घोषित किया। बुधवार को भोपाल में पीसी शर्मा ने बताया कि सरकार की खरीदी व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है। बार-बार खरीदी और स्टॉट बुकिंग की तारीख बढ़ने से सिस्टम की कमजोरी उजागर हो गई है। उन्होंने कहा कि खरीदी के शुरूआती 14 दिनों में सिर्फ 9.30 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीदी हुई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। किसान स्टॉट बुकिंग, पंजीयन पर्वी अपलोड और भुगतान में देरी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। कांग्रेस के इस आंदोलन से 11 जिलों के करीब 747 किलोमीटर क्षेत्र में यातायात प्रभावित होने की आशंका है। पार्टी ने इसे किसानों के हित में बड़ा आंदोलन बताया है, जबकि प्रशासन ने भी सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं।

किसानों को नहीं मिल रही मूलभूत सुविधाएं कांग्रेस का आरोप है कि खरीदी केंद्रों पर पेजल, छाया, बैटने और शीतालय जैसी मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं। किसानों को कई दिनों तक ट्रैक्टर-ट्रॉली के साथ सड़कों पर इंतजार करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि किसान मजबूरी में 1800 से 2022 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर व्यापारियों को गेहूँ बेच रहे हैं। पार्टी ने सरकार से मांग की है कि किसानों को 2625 रुपए प्रति क्विंटल का भाव दिया जाए और कम कीमत पर बेचे गए गेहूँ का अंतर भावांतर योजना के तहत सीधे खातों में जाला जाए।

# कहा-मेरे पास पैसे नहीं, ममता का चुनावी कैम्पेन इसी कंपनी ने संभाला था बंगाल हार के बाद अखिलेश ने आईपैक से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा



लखनऊ (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी ने चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी आई-पैक के साथ करार तोड़ दिया है। अखिलेश ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- हां, हमारा संबंध उनसे था। कुछ महीने हमारे साथ उन्होंने काम किया। लेकिन, अब हम साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फंड की कमी है, हम इतने फंड नहीं दे सकते हैं। अखिलेश ने कहा- कुछ लोगों ने हमें चुनाव जितवाने वाली कंपनी के बारे में बताया है। सलाह दी है कि सी-वोटर्स से सर्वे कराइए। एक कंपनी है, उसको साथ रखिए। सोशल मीडिया पर किसी के खिलाफ नकारात्मक प्रचार करना हो तो 360 डिली कंपनी से जुड़िए। उसको फंडिंग करिए। सपा मुखिया ने भाजपा सरकार पर तंज करते हुए कहा- सोच रहे हैं कि नेशन विथ नमो, जेविस जैसी कंपनियों से बात कर ली जाए।

# अब वंदे मातरम् को मिलेगा राष्ट्रगान जैसा दर्जा

● मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, कानून में संशोधन को मंजूरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। बंगाल चुनाव में बड़ी जीत के बाद केंद्र सरकार ने अपने पहले फैसले में वंदे मातरम् को लेकर बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हूँ कैबिनेट बैठक में राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण कानून में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस प्रस्ताव के तहत वंदे मातरम् को राष्ट्रगान जन गण मन के बराबर दर्जा देने की तैयारी है। अभी इस कानून के तहत राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान के अपमान या उसमें बाधा डालने पर सजा का प्रावधान है। संशोधन के बाद वंदे मातरम् को भी इस सूची में शामिल किया जाएगा, जिससे इसके नियमों का पालन न करने पर यह दंडनीय अपराध बन जाएगा।



कानून में बदलाव और सजा का प्रावधान

सरकार वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर यह बदलाव कर रही है। इसके लिए कानून की धारा 3 में संशोधन किया जाएगा। इस धारा के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगान गाने में बाधा डालता है या उसे रोकता है, तो उसे तीन साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। दोबारा अपराध करने पर कम से कम एक साल की सजा का प्रावधान है। संशोधन के बाद यही नियम वंदे मातरम् पर भी लागू होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले भी वंदे मातरम् को राष्ट्रगान के बराबर दर्जा देने की वकालत की थी। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि उसने इस गीत को राजनीति के कारण पीछे रखा। वंदे मातरम् का देश की आजादी की लड़ाई में खास महत्व रहा है। इसे बिक्रम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में अपने उपन्यास आनंदमठ में लिखा था।

# बीजेपी का हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है चुनाव

नई दिल्ली (एजेंसी)। राहुल गांधी ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लिखा, वोट चोरी से कभी सीटें सुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार। उन्होंने आगे तंज करते हुए लिखा, लोकसभा के 240 बीजेपी सांसदों में से, हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है।



# बंगाल में चुनाव बाद हिंसा, भारी बवाल

● कोलकाता में टीएमसी ऑफिस पर चला दिया बुलडोजर ● ममता और अभिषेक बनर्जी के घरों की हटाई गई सुरक्षा ● 24 घंटों में भाजपा-तृणमूल के 4 कार्यकर्ताओं की हत्या

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा शुरू हो गई है। कोलकाता के न्यू मार्केट में मंगलवार रात भीड़ ने टीएमसी के पार्टी ऑफिस को बुलडोजर से गिरा दिया। उपद्रवियों ने आसपास की दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया। टीएमसी ने घटना का वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा- भाजपा का 'परिवर्तन' बुलडोजर लेकर आया है।

कोलकाता में सीएम ममता के आवास, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर और टीएमसी हेडक्वार्टर से अतिरिक्त पुलिस तैनाती हटा दी गई है। तीनों जगहों पर बुधवार को कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं दिखा। ममता के आवास के बाहर लगे बैरिकेड भी हटाए गए हैं। अभिषेक डायमंड हार्वर सीट से सांसद हैं। उनकी जेड कैटेगरी सुरक्षा बहाल रहेगी।

संदेशखाली में सुरक्षाबलों पर फायरिंग, बम से भरा बैग मिला—नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेशखाली स्थित बामनधेरी इलाके में मंगलवार रात गश्त कर रही पुलिस और केन्द्रीय बलों पर हमला हुआ। उपद्रवियों ने फायरिंग की, जिसमें पांच सुरक्षाकर्मी घायल हो गए।

# सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 37 होगी

कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी, संसद के अगले सत्र में बिल पेश होगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार संसद के अगले सत्र में इससे जुड़ा विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल चीफ जस्टिस समेत 33 जजों की तय संख्या है। सरकार इसमें चार नए जज जोड़ना चाहती है। इसके लिए संसद के अगले सत्र में बिल लाया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद 1956 के कानून में संशोधन किया जाएगा। संविधान के



अनुच्छेद 124(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार संसद के पास है। कानून लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम नए जजों के नाम सरकार को भेजेगा। इससे पहले 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 31 से बढ़ाकर 33 की गई थी। वहीं, 2008 में जजों की संख्या 26 से बढ़कर 31 हुई थी। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के अलावा सिर्फ 10 जजों की व्यवस्था थी।



## 48 घंटे में खत्म हो सकती है ईरान-यूएस जंग

● 14 शर्तों का समझौता तैयार, अमेरिका ईरानी प्रॉपर्टी लौटाएगा ● ईरान पर दावा- होर्मुज खोलेगा और न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकेगा

तेहरान/वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिका और ईरान में युद्ध खत्म करने और परमाणु बातचीत का रास्ता तय करने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। अमेरिकी वेबसाइट एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान 48 घंटे के भीतर सीजफायर को लेकर सहमति दे सकता है। दोनों देशों के बीच 14 पॉइंट वाला समझौता तैयार है। हालांकि अभी यह फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन बातचीत पहले से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। सबसे पहले युद्ध खत्म करने की घोषणा होगी। 30 दिनों तक दोनों देशों की विस्तृत बातचीत होगी इसमें होर्मुज, परमाणु कार्यक्रम, अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील जैसे मुद्दे होंगे। दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए इस्लामाबाद या फिर



जिनेवा जैसे शहरों पर विचार हो रहा है। ड्राफ्ट के मुताबिक, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को कुछ समय के लिए रोक सकता है। बदले में अमेरिका धीरे-धीरे प्रतिबंध कम करेगा और ईरान के ज्वब किए हुए अरबों डॉलर जारी कर सकता है। साथ ही, होर्मुज में दोनों तरफ से लगाई गई पाबंदियों में भी ढील दी जाएगी। हालांकि सबसे बड़ा विवाद न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने की अवधि को लेकर है। ईरान 5 साल का प्रस्ताव दे चुका है, जबकि अमेरिका 20 साल चाहता था। अब बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, जिसमें 12 से 15 साल तक की अवधि पर बात चल रही है।



## संक्षिप्त समाचार

## छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से हाईवे डूबा, घरों में पानी

● यूपी के गाजियाबाद में ओले गिरे, यूपी-बिहार में बारिश

रायपुर (एजेंसी)। उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत में बारिश का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ में मंगलवार को भारी बारिश हुई। इससे कांकर के चारामा में नेशनल हाईवे-30 पर घुटनों तक पानी भर गया। मनेंद्रगढ़ के जनकपुर में बारिश का पानी लोगों के घर में घुस गया। पेंड्रा में आंधी से कई पेड़ टूटकर गिर गए। यूपी के गाजियाबाद में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। बारिश के कारण पूरे यूपी में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे आ गया है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। राजस्थान में बाड़मेर और फालोदी को छोड़कर



बाकी सभी शहरों में तापमान 40 डिग्री से नीचे रहा। इधर, बिहार और मध्य प्रदेश में भी बारिश का दौर जारी है। बिहार में पिछले 24 घंटे में 89.7 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 182 फीसदी अधिक है। राज्य में 7 मई तक आंधी-बारिश जारी रहेगी। एमपी के 28 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट है। उत्तर भारत में फिर से गर्मी शुरू होने की संभावना- भारतीय मौसम के लिहाज से आने वाले दिन काफी उथल-पुथल भरे साबित हो सकते हैं। एक तरफ जहां अरब सागर में मानसून-पूर्व चक्रवाती तूफान के संकेत मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राहत दे रही बारिश और तेज हवाओं के थमने के बाद उत्तर भारत में गर्मी का नया दौर शुरू होने का संकेत है। देश के अधिकांश हिस्सों में आंधी और बारिश का दौर जारी है।

## तमिलनाडु में विजय को मिलेगा 'हाथ' का साथ

● टीवीके के साथ नई सरकार बनाने की तैयारी में कांग्रेस

नई दिल्ली (एजेंसी)। तमिलनाडु में कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए टीवीके नेता विजय का समर्थन करने का फैसला किया है। टीवीके का समर्थन करने का यह फैसला मंगलवार देर रात तमिलनाडु कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति की एक आपात बैठक में लिया गया। पार्टी के तमिलनाडु मामलों के प्रभारी गिरीश चोडनकर ने टीवीके को समर्थन देने पर फैसला करने के लिए समिति की यह बैठक बुलाई थी। सूत्रों ने बताया कि यह बैठक टीवीके पर आयोजित की गई थी और वरिष्ठ सदस्यों ने अभिनेता से राजनेता बने विजय का समर्थन करने के पक्ष में



अपने विचार बताए। इसके साथ ही सूत्रों ने पुष्टि की कि तमिलनाडु कांग्रेस की टीम ने तमिलनाडु में एक धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाने के लिए टीवीके नेता विजय का समर्थन करने का सर्वसम्मति से फैसला किया। इससे पहले, कांग्रेस ने दावा किया था कि विजय ने राज्य में सरकार बनाने के लिए उसका समर्थन मांगा है और बताया कि उसके नेतृत्व में राज्य इकाई को इस मामले पर अंतिम फैसला लेने का निर्देश दिया है, जिसमें राज्य की भावनाओं को ध्यान में रखा जाएगा। कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं की माने तो उन्होंने कहा, सरकार बनाने के लिए डीएमके के साथ गठबंधन में विधानसभा चुनाव जरूर लड़ा गया था, लेकिन दक्षिणी राज्य में एक धर्मनिरपेक्ष सरकार के लिए है और उससे भी जरूरी किसी भी तरह से बीजेपी और उसके प्रतिनिधियों को तमिलनाडु की सरकार नहीं चलाने देने के लिए यह कदम उठाया गया है।

## ममता बनर्जी के आवास के बाहर से हटी सुरक्षा बैरिकेडिंग

● अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर भी घटाई गई सिक्वोरिटी



कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद बदलाव की बयार बहनी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो अपने गढ़ भवानीपुर में भी जीत हासिल नहीं कर पाईं, उनके आवास के बाहर से सुरक्षा घेरे को कम कर दिया गया है। सत्ता परिवर्तन के 24 घंटे बाद ही मुख्यमंत्री आवास के आसपास की सड़कों को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। यह रास्ते बंद कड़े वर्षों से सुरक्षा के मद्देनजर प्रतिबंधित क्षेत्र थे। कालीघाट स्थित 30वीं हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर सीएम ममता के आवास तक जाने वाले रास्ते पर वर्षों से मौजूद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तेजी से हटती नजर आई। हाजरा क्रॉसिंग के पास हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर लगी बैरिकेडिंग को हटा दिए गए हैं। वहीं, जो पुलिसकर्मी पहले लोगों की आवाजाही नियंत्रित करते थे वह सब वहां से गायब दिखाई दिए।

## असम में 12 मई को शपथ, पीएम मोदी रहेंगे मौजूद

दिसपुर (एजेंसी)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की और उन्हें इस्तीफा सौंप दिया। फिलहाल वह नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार संभालेंगे। जानकारी मिल रही है कि नई सरकार का शपथ समारोह 12 मई को होगा और इस आयोजन में पीएम नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के तमाम सीनियर नेता मौजूद रहेंगे। सूत्रों का कहना है कि लगातार तीसरी बार हिमंत बिस्वा सरमा को ही मुख्यमंत्री का पद मिलने की संभावना है। हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद एक फिर से राज्य की जनता का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि असम के लोगों ने हमारी सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने पीएम मोदी के प्रति अपना समर्थन जताया है। जनता चाहती है कि असम में विकास की गंगा बह रही है, वह जारी रहे।

## विजय सिन्हा को मिलेगी लॉ एंड ऑर्डर की कमान!

● बिहार के सियासी गलियारे में गृह विभाग पर चर्चा तेज

पटना (एजेंसी)। बिहार की राजनीति मिल सकता है। बिहार में सोशल मीडिया साइट्स समझने और नब्ब पकड़ने में तो कई पर आपको कई ऐसे पोस्ट दिखेंगे, जिसमें एक्सपर्ट भी मात खा जाते हैं। 2015 विजय कुमार सिन्हा के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें गृह विभाग दिया जा सकता है। यानी पूरे बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की कमान। इसके समर्थन में तर्क दिए जा रहे हैं कि विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व भूमि सुधार विभाग में लगे भ्रष्टाचार के चुन को पीसने में एड़ी भविष्यवाणी जोंरों पर है, इसे चर्चा ही कहें तो चोटी एक कर दी। सम्राट चौधरी के सीएम बनते बेहतर है कि विजय कुमार सिन्हा को गृह मंत्रालय



● डीजीपी बोले-पाक का हाथ, सीएम ने कहा-बीजेपी ने करा

## पंजाब में आर्मी कैम्प-बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर ब्लास्ट

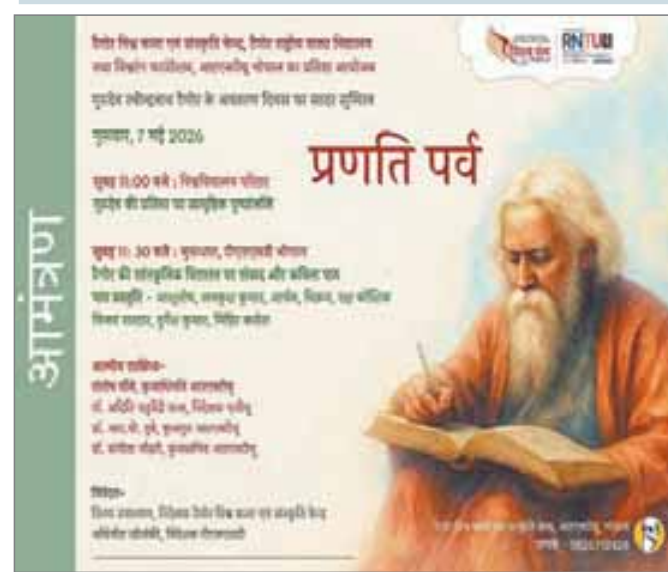
चंडीगढ़ (एजेंसी)। जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर मंगलवार रात धमाका हुआ। इसमें इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के इस्तेमाल की बात कही जा रही है। गनीमत रही कि धमाके में किसी को चोट नहीं लगी। इस ब्लास्ट का वीडियो भी सामने आया है। वहीं, अमृतसर में आर्मी कैम्प के भीतर भी ग्रेनेड अटैक की कोशिश की गई, लेकिन वह दीवार पर टकराकर फट गया। डीजीपी गौरव यादव ने अमृतसर पहुंचकर मौके का जायजा लिया। उन्होंने माना कि जालंधर व अमृतसर में आईडी ब्लास्ट हुए। कहा कि जालंधर में संभव है कि टाइमर या रिमोट से ब्लास्ट किया गया हो।



इसमें पाकिस्तान खुफिया एजेंसियों का हाथ है। ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी की वजह से धमाके कराए गए हो सकते हैं। डीजीपी अब जालंधर पहुंचे हैं। वहीं, श्री आनंदपुर साहिब से शुकुराना यात्रा के दौरान पंजाब सीएम भगवंत मान ने कहा कि ये ब्लास्ट भाजपा के इलेक्शन की तैयारी हैं। भाजपा छोटे-मोटे ब्लास्ट करवाकर लोगों को डराकर वोट लेना चाहती है। यह भाजपा का स्ट्राइल है। चुनाव वाले स्टेट में ब्लास्ट और दंगे करवा दो।

## गुरुदेव की जयंती पर आज 'प्रणति पर्व'

टैगोर की सांस्कृतिक विरासत पर संवाद और रचनापाठ



भोपाल। गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर की जयंती पर 'प्रणति पर्व' का आयोजन टैगोर विश्व कला एवं संस्कृति केन्द्र द्वारा गुरुवार, 7 मई को किया जा रहा है। इस अवसर पर गुरुदेव की सांस्कृतिक विरासत पर संवाद और उनकी चर्या कविताओं का पाठ होगा। टैगोर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के विद्यार्थी आशुतोष, लवकुश कुमार, आर्यन, विक्रम, दक्ष कौशिक विजय सरदार, दुर्गा कुमारी, एवं मिहिर कसेरा टैगोर की कविताओं का वाचन करेंगे। टैगोर कला केन्द्र के निदेशक विनय उपाध्याय ने बताया कि 'प्रणति पर्व' में गुरुदेव के गीतों पर आधारित दृश्य-श्रव्य रूपक 'गीतांजलि' पर केन्द्रित बहुरंगी पुस्तिका का लोकार्पण भी किया जाएगा। समारोह का आरंभ रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्व विद्यालय में स्थापित टैगोर प्रतिमा पर सामूहिक पुष्पांजलि से होगा। उसके उपरान्त 'मुक्तधारा' सभागार में सांस्कृतिक सभा होगी।

रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं साहित्यकार संतोष चोबे, एजीयू की निदेशक डॉ. अदिति चतुर्वेदी वल्लभ, कुलगुरु डॉ. आर.पी. दुबे और कुलसचिव डॉ. सीता जीहरी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। समारोह का आयोजन विश्वरंग फाउंडेशन और टैगोर राष्ट्रीय नाट्य, विद्यालय के सहयोग से किया जा रहा है। टैगोर विश्व कला एवं संस्कृति केन्द्र, आरएनटीयू द्वारा जारी।

## कार्यकर्ताओं से संवाद कर जनसमस्याओं का किया त्वरित समाधान



भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग एवं मंत्री श्री लखन पटेल ने बुधवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश भर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। मध्यप्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग एवं मंत्री श्री लखन पटेल ने प्रदेश भर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं एवं आमजनों से संवाद कर उनकी जनसमस्याओं का त्वरित समाधान किया। जिन समस्याओं का तत्काल समाधान नहीं किया जा सका, उन्हें संबंधित विभागों को निराकरण के लिए भेजा गया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए उनकी कठिनाइयों को समझा और उन्हें जल्द से जल्द समाधान दिलाने का आश्वासन दिया।

## अमृतसर में आर्मी कैम्प पर हमले से टीन शेट डह

करीब 3 घंटे बाद अमृतसर में आर्मी कैम्प खासा के बाहर मंगलवार रात करीब 11 बजे ग्रेनेड अटैक हुआ। अमृतसर रूरल के एसपी सोहेल मीर कासिम के मुताबिक बाइक पर सवार 2 नकाबपोशों ने आर्मी कैम्प की तरफ फेंका। दीवार के साथ लगते ही जोरदार धमाका हुआ। धमाके से चारदीवारी पर सेना एरिया को कवर करने के लिए लगाया गया टीन शेट डह गया। गेट नंबर 6 और 7 के बीच की दीवार को भी थोड़ा नुकसान हुआ है।

## जालंधर में कूरियर बॉय की ऐक्टिवता में हुआ ब्लास्ट

जालंधर में बीएसएफ चौक के पास रात 7.57 बजे एक स्कूटी के पास धमाका हुआ। पुलिस जांच में एक सदिश चौक की ओर से रॉन्ग साइड से पैदल आता दिखा। वह सीधे उस स्थान तक पहुंचा, जहां फुटपाथ पर ऐक्टिवता खड़ी थी। युवक ने पॉलिथीन में लिपटा पैकेट वहां छोड़ा और बस अड्डे की ओर दौड़ लगा दी। इसके कुछ सेकंड में धमाका हो गया। जिस ऐक्टिवता में धमाका हुआ, वह बीएसएफ के ही रिटायर्ड जवान कश्मीर सिंह की है। उसका बेटा गुरप्रीत सिंह पार्सल लेने के लिए आया था। हेलमेट न पहने होने की वजह से जवानों ने उसकी ऐक्टिवता बाहर खड़ी करा दी। गुरप्रीत अभी पुलिस हिरासत में है।

# मेट्रो से अब जश्नों से होगी कमाई, ट्रेन के डिब्बों में मनाएंगे बर्थडे, प्री वेडिंग

इंदौर। लंबे समय से प्रतीक्षित मेट्रो परियोजना का एक बड़ा हिस्सा तैयार हो चुका है, लेकिन यात्रियों के लिए इसकी शुरुआत अब तक नहीं हो सकी है। सुपर कारिडोर से रैडिसन चौराहे तक लगभग 17 किलोमीटर लंबे वायडक्ट का निर्माण पूरा हो चुका है, जिस पर करीब 5800 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बावजूद संचालन शुरू न होने से परियोजना से कोई आय नहीं हो पा रही थी, जिससे प्रबंधन के सामने आर्थिक चुनौती खड़ी हो गई। इसी स्थिति को देखते हुए मेट्रो प्रशासन ने अब एक नया और अलग तरह का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। 'सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स' नाम से शुरू की जा रही इस योजना के तहत मेट्रो ट्रेन के डिब्बों और स्टेशन परिसर को निजी और व्यावसायिक आयोजनों के लिए किराए पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब मेट्रो केवल यात्रा का साधन ही नहीं रहेगी, बल्कि यह लोगों के खास पलों की मेजबानी भी करेगी।

## कोच में होंगे आयोजन

इस योजना के तहत जन्मदिन समारोह, किटी पार्टी, प्री-वेडिंग शूट जैसे आयोजन मेट्रो कोच में किए जा सकेंगे। इसके अलावा फिल्मों, धारावाहिकों, विज्ञापनों और फोटोशूट की शूटिंग के लिए भी अनुमति दी

## संचालन से पहले 'सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स' योजना से मिलेगा सहारा



जाएगी। मेट्रो अधिकारियों का कहना है कि इन आयोजनों को इस तरह से संचालित किया जाएगा कि भविष्य में यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। शुल्क की व्यवस्था भी तय कर दी गई है। यदि कोई व्यक्ति या समूह स्टेशन परिसर में खड़े मेट्रो कोच का उपयोग करना चाहता है, तो उसे 5000 रुपये प्रति घंटे का भुगतान करना होगा। वहीं, यदि आयोजन चलती

मेट्रो में करना है तो इसके लिए 7000 रुपये प्रति घंटे शुल्क देना होगा। एक कोच में एक समय में अधिकतम 50 लोगों को अनुमति दी जाएगी। इससे अधिक संख्या होने पर अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। साथ ही प्रत्येक कोच के लिए 20 हजार रुपये की सुरक्षा राशि जमा करनी होगी, जो सभी नियमों का पालन करने पर वापस कर दी जाएगी।

## आवेदन की प्रक्रिया

मेट्रो का संचालन शुरू होने में देरी का मुख्य कारण उद्घाटन कार्यक्रम का टलना रहा है। मार्च महीने में इसके उद्घाटन की पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन चार राज्यों में चुनाव होने के कारण प्रधानमंत्री कार्यालय से अंतिम तारीख तय नहीं हो सकी। इसी वजह से परियोजना फिलहाल शुरू होने का इंतजार कर रही है। बुकिंग प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि लोग आसानी से इस सुविधा का लाभ उठा सकें। इच्छुक लोगों को आयोजन से कम से कम 15 दिन पहले आवेदन करना होगा। बुकिंग 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध रहेंगे। मेट्रो प्रशासन की उम्मीद है कि इस नई पहल से न केवल खाली पड़े संसाधनों का उपयोग हो सकेगा, बल्कि संचालन शुरू होने से पहले ही कुछ हद तक आय भी प्राप्त होगी। इसके साथ ही शहर के लोगों को एक अनोखा अनुभव भी मिलेगा, जहां वे अपने खास अवसरों को एक अलग अंदाज में मना सकेंगे।

## शहर में पानी बना सबसे बड़ा संकट, टैंकर के पीछे दौड़ लगा रहे रहे लोग

10 मिनट की सप्लाई में गुजारना दिन, 500 का टैंकर 1000 तक पहुंचा

इंदौर। भीषण गर्मी के बीच शहर में पानी अब सबसे बड़ी समस्या बन गया है। तापमान 44 डिग्री के करीब पहुंचते ही जल संकट ने विकराल रूप ले लिया है। हालात ऐसे हैं कि हर सुबह लोगों की शुरुआत पानी के इंतजार से हो रही है। कहीं टैंकर के पीछे भीड़ दौड़ रही है, तो कहीं लोग घंटों लाइन में खड़े होकर बर्तन भर रहे हैं। सबसे ज्यादा असर पानी के दामों पर पड़ा है। जो टैंकर पहले 500 रुपए में मिल जाता था, अब उसकी कीमत 800 से 1000 रुपए तक पहुंच गई है। मांग ज्यादा और सप्लाई कम होने का फायदा उठाकर निजी टैंकर संचालक मनमाना कर रहे हैं। शहर में नल से पानी की सप्लाई भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। पहले जहां करीब एक घंटे पानी आता था, अब वह घटकर महज 10 मिनट रह गया है। नर्मदा लाइन से आने वाली सप्लाई कम होने से कई इलाकों में पानी पहुंच ही नहीं रहा।

## पोशा कॉलोनियां भी बेहाल

द्वारकापुरी, समाजवादी इंदिरा नगर, विजय नगर, सुखलिया, सहित कई पोशा क्षेत्रों में भी जल संकट गहराया है। बोरींग सूख चुके हैं और लोग सुबह 4 बजे उठकर पानी जुटाने को मजबूर हैं। रहवासियों का कहना है कि पार्श्व से गुहार के बावजूद पर्याप्त टैंकर नहीं मिल रहे। ऐसे में पानी अब जरूरत नहीं, बल्कि रोज की जंग बन गया है।

## हवाई यात्रा में लापरवाही या चोरी, इंदौर आए यात्री का सामान टूटा

इंदौर। मुंबई से आए एक व्यापारी का कीमती सामान उड़ान के दौरान रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। यह घटना एयर इंडिया की उड़ान संख्या एआई-2591 से जुड़ी है। शिकायतकर्ता हिमांशु गुप्ता, जो श्रीनाथ रेजीडेंसी के निवासी और फर्नीचर व्यवसाय से जुड़े हैं। बताया कि उन्होंने 2 मई की सुबह करीब 4 बजे अपने दो बैग हवाई अड्डे पर जमा कराए थे। उनकी उड़ान सुबह 7 बजे 25 मिनट पर रवाना हुई और करीब 9 बजे इंदौर पहुंचे। यात्रा सामान्य रही, लेकिन असली परेशानी तब शुरू हुई जब उन्होंने सामान प्राप्त किया।

## कीमती सामान गायब

जब हिमांशु ने बैगें पट्टी क्रमांक-2 से अपना बड़ा सूटकेस उठाया, तो उसका ताला टूटा हुआ था और जंजीर खुली हुई थी। यह देखकर वे हैरान रह गए। सूटकेस खोलने पर पता चला कि उसमें रखी कीमती वस्तुएं गायब हैं। इनमें एक महंगी राइफे घड़ी, इत्र की बोतलें और दो चमड़े की पेटियां शामिल थीं। हिमांशु के अनुसार, जब उन्होंने सामान जमा कराया था, तब वह पूरी तरह सुरक्षित और बंद अवस्था में था। इस स्थिति ने संदेह को और गहरा कर दिया कि

## बंद सूटकेस से घड़ी, इत्र और चमड़े की पेटियां गायब



चोरी यात्रा के दौरान या सामान के रखरखाव के समय हुई है।

नहीं मिला सही जवाब- घटना का पता चलते ही उन्होंने तुरंत वहां मौजूद हवाई सेवा

कर्मियों और सुरक्षा कर्मचारियों को जानकारी दी। उन्होंने पूरी घटना का वीडियो भी बनाया और मौके पर जवाब मांगा, लेकिन उन्हें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। पीड़ित का कहना है कि जब उन्होंने

वहीं पर चोरी की रिपोर्ट बनवाने की बात कही, तो उन्हें मना कर दिया गया। बाद में हवाई सेवा की ओर से उनसे वही रिपोर्ट मांगी गई, जिससे वे और अधिक परेशान हुए। उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी संदेश के माध्यम से और सार्वजनिक मंचों पर भी साझा की।

## पुलिस जांच शुरू

आखिरकार हिमांशु गुप्ता ने मामले की शिकायत स्थानीय इंदौर पुलिस के एरोइम थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हवाई सेवा से जुड़े कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि चोरी किस चरण में हुई। हवाई अड्डा प्रबंधन ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है।



## मुस्लिम महिलाओं ने निभाया मानवता का फर्ज, प्रसूता की 5 दिन तक सेवा

इंदौर। जहां एक ओर समाज में धर्म और जाति के नाम पर विभाजन की खबरें सामने आती रहती हैं, वहीं इंदौर से इंसानियत और भाईचारे की एक ऐसी मिसाल सामने आई है, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। प्रकाश चंद सेटी अस्पताल में खजराना क्षेत्र की दो मुस्लिम महिलाएं शमशाद मंसूरी और सलमा बी ने जरूरतमंद प्रसूता की सेवा कर मानवता की मिसाल पेश की। जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश निवासी सुंदरी अपने पति घनश्याम के साथ इंदौर में रहती हैं। प्रसव के दौरान अस्पताल में उनके साथ कोई परिजन मौजूद नहीं था, जिससे वह बेहद घबराई हुई थीं। ऐसे मुश्किल समय में शमशाद और सलमा ने आगे बढ़कर न केवल उनका हीसला बढ़ाया, बल्कि पूरे 5 दिनों तक बारी-बारी से दिन-रात उनके साथ रहकर देखभाल की। इस दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं से लेकर हर छोटी-बड़ी जरूरत का ध्यान रखा गया। यहां तक कि जब प्रसूता को रक्त की आवश्यकता पड़ी, तो शमशाद के परिजनों ने रक्तदान कर मदद की। दोनों महिलाओं की इस निस्वार्थ सेवा ने यह संदेश दिया कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। इंदौर की यह घटना आज भी समाज में जिंदा भाईचारे और आपसी सद्भाव की मजबूत तस्वीर पेश करती है।

## जल संरक्षण ने रफ्तार पकड़ी

इंदौर। जिले में जल संरक्षण को नई गति देने के लिए 'जल गंगा संवर्धन अभियान' के द्वितीय चरण की तैयारियां तेज हो गई हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा ने कलेक्टर कार्यालय में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर शहर सहित देवालगढ़, मह और सांवेर क्षेत्रों में चल रहे कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में तालाबों के गहरीकरण व शुद्धिकरण, पुराने बावड़ियों के जीर्णोद्धार, हैंडपंप सुधार और वाटर हार्वैस्टिंग जैसे कार्यों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी कार्य तय समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं, ताकि जल संरक्षण के प्रयास प्रभावी बन सकें। साथ ही निर्णय लिया गया कि जीर्णोद्धार के बाद बावड़ियों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर जन-जागरूकता बढ़ाई जाएगी।

## सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती शुरू चौपाटी पर लगी स्वच्छता की चौपाल

### स्कीम-140 को 'आदर्श प्लास्टिक फ्री चौपाटी' बनाने की पहल

इंदौर। शहर को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने के अभियान को तेज करते हुए नगर निगम ने स्कीम नंबर 140 चौपाटी पर 'सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री मार्केट अवेयरनेस चौपाल' आयोजित की। महापौर पुष्पमित्र भार्गव और आयुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देश पर हुए इस कार्यक्रम में अपर आयुक्त प्रखर सिंह के नेतृत्व में अधिकारियों, एनजीओ प्रतिनिधियों और व्यापारियों की सक्रिय भागीदारी रही। चौपाल में सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों पर विस्तार से जानकारी दी गई और इसके उपयोग को पूरी तरह बंद करने की अपील की गई। अपर आयुक्त ने क्षेत्र का भ्रमण कर दुकानदारों से सीधे संवाद किया और

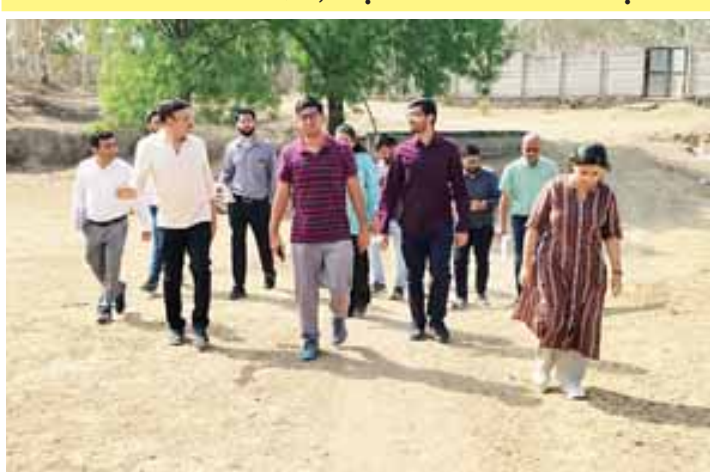


बायोडिग्रेडेबल विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही हर दुकान के बाहर गीले-सूखे कचरे के लिए दो डस्टबिन रखने के निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान व्यापारियों और आमजन ने स्वच्छता की सामूहिक शपथ ली। सभी ने स्कीम-140 चौपाटी को आदर्श, स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने में सहयोग का भरोसा दिया। निगम ने भी नियमित निगरानी और सख्त कार्रवाई के संकेत दिए।

## आवास योजना 2.0 को रफ्तार मिली आयुक्त ने साइट्स निरीक्षण किया

### सनावदिया, बढ़िया कीमा और उमरी खेड़ा में तैयारियों का जायजा

इंदौर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहर में किरफायती आवास परियोजनाओं को गति देने के लिए नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान अपर आयुक्त अर्थ जैन, ईई मितेश सिंगोड, यंत्री अभिनव और कंसल्टेंट टीम भी मौजूद रही। आयुक्त ने सनावदिया, बढ़िया कीमा और उमरी खेड़ा क्षेत्रों में जमीन की उपलब्धता, पहुँच मार्ग, बुनियादी सुविधाओं और परियोजनाओं के क्रियान्वयन की संभावनाओं का बारीकी से मूल्यांकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र हितग्राहियों को जल्द से जल्द आवास उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रक्रियाएं तय समय सीमा में पूरी की जाएं और कार्य में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए।



## दो परियोजनाओं को मंजूरी

नगर निगम द्वारा पीएमवाय 2.0 के तहत कुल 5 डीपीआर शासन को भेजी गई हैं। इनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6048, 2 बीएचके के 1368 और 3 बीएचके के 720 आवास प्रस्तावित किए गए हैं। तापी परिसर ट्रेजर फेस्टीसी और बढ़िया कीमा की दो परियोजनाओं को केंद्र सरकार से मंजूरी भी मिल चुकी है। अधिकारियों के अनुसार, मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इससे शहर के हजारों जरूरतमंद परिवारों को अपने घर का सपना साकार करने का अवसर मिलेगा और शहरी आवास व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।

## दो शिक्षकों को कलेक्टर ने सम्मानित किया



इंदौर। जनगणना कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दो शासकीय शिक्षकों को बुधवार को कलेक्टर शिवम वर्मा ने सम्मानित किया। जहां एक ओर कई कर्मचारी ड्यूटी से बचने के लिए कारण प्रस्तुत कर रहे हैं, वहीं इन शिक्षकों ने जिम्मेदारी निभाकर उदाहरण

पेश किया। कलेक्टर हालांकि शिक्षिका निर्मला शर्मा ने दोनों चुटनों के ऑपरेशन के बावजूद तय समय से पहले जनगणना कार्य पूरा किया। वहीं बिचोली क्षेत्र के शिक्षक बदीलाल तड़ोला ने अपने क्षेत्र के सभी गांवों में सबसे पहले कार्य पूर्ण कर सराहना हासिल की।

कलेक्टर ने दोनों को शाल, श्रीफल और पुष्पमाला भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने उनके समर्पण की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह उपलब्धि अन्य कर्मचारियों के लिए प्रेरणादायक है। यह सम्मान उनकी मेहनत और कर्तव्यनिष्ठा का प्रतीक है।

# आखिर कैसे आए ये चुनाव परिणाम

## संपादकीय ममता बैनर्जी का बाल हट !

विधानसभा का पूरा चुनाव और खुद अपनी भवानीपुर सीट हार जाने के बाद भी परिचम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी का यह कहना कि हार के बाद भी उनकी नैतिक जीत हुई है, और इसी आधार पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न देने की जिद शुद्ध रूप से बाल हट और संविधान का अपमान है। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक उन्होंने पद से त्यागपत्र देने की औपचारिकता पूरी नहीं की थी। जबकि एक विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद चुनाव जीतने के बावजूद मुख्यमंत्री को पहले पद से त्यागपत्र देना होता है और उसके बाद ही वह फिर से सीएम पद की शपथ ले सकता है। कौन चुनाव हारा है, कौन नहीं यह तो चुनाव आयोग द्वारा जारी प्रमाण पत्र से ही तय होता है न कि किसी नेता के कहने या मान भर लेने से। कायदे से चुनाव हारते ही ममता बैनर्जी को लोकभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए था। नैतिकता का तकाजा भी यही है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने अपनी हार के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि कोई उनसे जबर्दस्ती इस्तीफा नहीं ले सकता। उन्होंने चुनाव आयोग को असली विलेन बताया। ममता ने यह भी कहा कि वो 'पाटी सदस्यों के साथ आगे की स्ट्रेटजी पर चर्चा करेंगे। और मैं अब बीजेपी के अत्याचारों को और बर्दाश्त नहीं करूँगी।' मैं सड़कों पर लौटूंगी। उभर ममता के इस अडिगल रवै पर बीजेपी प्रवक्ता देवजीत सहनाने ने कहा कि ममता ऐसी बातें बोलकर खुद को ही हास्यास्पद बना रही हैं। इस तरह की हास्यास्पद बातों का कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी या संविधान में विश्वास करने वाली कोई पार्टी नहीं दे सकती। अगर ममता इस्तीफा नहीं देतीं तो क्या इससे राज्य में कोई संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है? गौरतलब है कि संविधान का अनुच्छेद 164 राज्य के मंत्रिपरिषद के गठन और इसमें राज्यपाल की शक्तियों से जुड़ा हुआ है। संविधान का अनुच्छेद 164 ( 1 ) कहता है कि मुख्यमंत्री 'राज्यपाल की इच्छा तक' पद पर बने रह सकते हैं। राज्यपाल की इच्छा क्या होती है? इस बारे में संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि राज्यपाल की 'इच्छा' दरअसल निर्वाचित प्रतिनिधियों (विधायकों) के बहुमत द्वारा किसी एक नेता पर जलाए गए भारों से तय होती है। हर चुनाव के बाद राज्यपाल विधानसभा में दलों की संख्या का आकलन करते हैं और बहुमत वाली पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। अगर मौजूदा मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देतीं तो राज्यपाल अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकते हैं, जिसका हिस्सा मुख्यमंत्री भी होते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडलों (विधानसभा और विधान परिषद) के कार्यकाल को तुरीख है। इसके मुताबिक उस विधानसभा का कार्यकाल पहली बैठक की जारीख से पांच वर्ष का होता है। पांच साल का वक़्त पूरा होते ही यह खुद व खुद भंग हो जाएगा। ऐसे में ममता बैनर्जी का कार्यकाल खतम: समाप्त हो जाएगा। ममता भी यह अच्छी तरह से जानती हैं। लेकिन लगता है कि वो विक्टिम कार्ड खेलना चाहती हैं ताकि राज्यपाल उन्हें मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त करें और वो जनता की सहानुभूति बटोर सकें। वैसे भी चुनाव हारने पर सीएम का त्यागपत्र एक संवैधानिक औपचारिकता है। अगर ममता इस मर्यादा का भी पालन नहीं करतीं तो भी नई सरकार के गठन पर इसका कोई असर नहीं होगा। ममता अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। अगर वो पद से इस्तीफा दे भी दें तो राज्यपाल उन्हें अपने मुख्यमंत्री की शपथ तक कार्य करने को कह सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद खाली नहीं रह सकता।



**नजरिया**  
**अवधेश कुमार**  
लेखक दिल्ली निवासी वरिष्ठ पत्रकार हैं।

पाँच राज्यों के चुनाव परिणामों पर कोई एक सुसंबद्ध टिप्पणी संपूर्ण स्थितियों का विश्लेषण नहीं कर सकता। किंतु सबको मिलाकर एक तस्वीर बनाएँ तो इसमें दो ऐतिहासिक युगांतरकारी परिणतियाँ हैं। एक, पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐसी विजय जो एक समय अकल्पनीय थी तथा तमिलनाडु में थलापति विजय की पार्टी टीवीके का चमत्कारिक प्रदर्शन। वैसे तो असम में भी भाजपा की तीसरी बार लगातार विजय महत्वपूर्ण है पर ये दोनों घटनाएँ ऐतिहासिक और युगांतरकारी हैं। बंगाल में एक तिहाई मुस्लिम मतदाताओं के बहुमत का हर हाल में भाजपा को सता में आने से रोकने और तृणमूल के समर्थन में आक्रामकता से काम करने के बावजूद भाजपा की इतनी बढ़त सामान्य घटना नहीं है। आम सोच यही थी कि ममता की शुरुआत ही 30 प्रतिशत मत और लगभग 65-70 सीटों से होती है जबकि भाजपा को शून्य से शुरुआत करनी होगी। वैसे असम में इससे ज्यादा मुस्लिम आबादी के बावजूद भाजपा ने जीत हासिल कर कई मिथकों को तोड़ा। पर असम और बंगाल की राजनीति और सत्ता के चरित्र में मौलिक अंतर है। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूरी राजनीति और सत्ता का चरित्र ऐसा बना दिया था जिसमें किसी भी पार्टी के लिए उसको भेदना असंभव सी चुनौती थी।

पिछले एक दशक से ज्यादा समय के चुनावों का एक पहलू हर जगह लागू होता है वह यह कि हिंदुत्व व अपनी संस्कृति, धर्म के प्रति हिंदुओं के पुनर्जागरण के कारण एक निश्चित वोट का आधार हर राज्य में निर्मित हो गया है और यह मत भाजपा से संतुष्ट असंतुष्ट या कुछ मायनों में नाराज होने के बावजूद वह हारे या जीते जा साथी दलों या उसकी अनुसंधितियों में दूसरे दलों को जाता है। यह प्रवृत्ति पाँचों राज्यों में रही है। भाजपा स्थानीय-क्षेत्रीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए भी चुनावों को मतदाताओं को सीधे अपील करने वाले राष्ट्रीय विषयों के साथ संबद्ध करती है। भाजपा ने राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसांख्यिकी को बंगाल एवं असम दोनों जगह प्रमुख मुद्दों के रूप स्थापित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान संबंधी कार्यों तथा नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण को लागू करने की संसदीय पहल ने भी चुनावी माहौल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

बंगाल के परिणाम ने केवल उन्हें चौंकाया है जो जमीनी वास्तविकता और 2018 से मतदाताओं मुख्यतः हिन्दुओं के बड़े वर्ग के अंदर बदलाव की छटापट्टक को महसूस नहीं कर रहे थे। तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के नेतृत्व में सत्ता

और पूरी राजनीति को निहत स्वार्थी तत्वों की गिरफ्त में दिए जाने से बंगाल की संस्कृति चुनावों को हर हाल में अपने पक्ष में करने की हो चुकी है। कट्टरपंथी तत्वों को प्रत्यक्ष- परोक्ष संरक्षण और प्रोत्साहन के कारण पूरा प्रदेश हमेशा सांप्रदायिक भय और तनाव की स्थिति में रहा। मतदाताओं की इच्छा नहीं तृणमूल नेताओं की चाहत से आम मतदान करिए या चुनाव घर बैठिये अन्यथा हिंसा, आगजनी, दमन, उरगीड़ और संबंधित स्थान या प्रदेश से पलायन का दर्श झेलिये। साइलेंट रीगिंग बंगाल की मुख्य चुनावी प्रवृत्ति रह रही है। पहले इसी रास्ते वाम मोर्चा ने लगातार जीत सुनिश्चित किया और उसके विरुद्ध लंबा संघर्ष करते-करते ममता बनर्जी ने भी अपनी पूरी पार्टी को उससे ज्यादा हिंसक और दमनकारी तत्वों में परिणत कर दिया। पलायन या हिंसा की सर्वाधिक शिकार महिलाएं होती हैं। पुरुषों के मुकाबले 1.5 प्रतिशत महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया। महिला होने के बावजूद ममता बनर्जी के विरुद्ध इनका बहुत बड़ा मत भाजपा को गया है। भाजपा पर धुवीकरण का आरोप लगाकर सतही विश्लेषण करने वाले विचार करें कि भद्र लोक माने जाने वाले बंगाल के हिंदुओं ने ममता बनर्जी की सत्ता संस्कृति के विरुद्ध विद्रोह कर भाजपा को मत दिया तो क्या इसे केवल धुवीकरण कहेंगे और ऐसा हुआ भी तो क्यों?

बंगाल में राजनीतिक संघर्ष वास्तविक लोकतंत्र की पुनर्स्थापना तथा सत्ता संस्कृति को सर्वसमावेशी बनाने का था। यह जिम्मेवारी मुख्यतः प्रदेश के गैर मुस्लिमो यानी हिंदुओं को ही लेना था। हिंदुओं के अंदर अगर यह भाव पैदा हुआ कि इस सरकार के रहते हमारा अस्तित्व संकट में है तो इसके कारण अत्यंत गहरे हैं। बांग्लादेश की घटनाओं ने इस मनोकथित को सशक्त किया कि हमें कुछ हद तक जान की बाजी लगानी होगी। हिंदू आबादी में लगभग 75 प्रतिशत ने भाजपा के पक्ष में वोट दिया है। यह बहुत बड़ी बात है। एसआईआर में 90 लाख से ज्यादा मृत, सदिध और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जाने के कारण फ्रॉनी मतदाताओं का खेल खत्म हो गया। सवा 2 लाख केंद्रीय बलों की उपस्थिति, चुनाव के बाद भी सुरक्षा बलों के बने रहने की घोषणा, दूसरे राज्यों के अधिकारियों को चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति, प्रदेश के अधिकारियों का व्यापक पैमाने पर स्थानांतरण या चुनाव प्रक्रिया तक कार्य व्युत्पन्न तथा चुनावी हिंसा वाले चिन्हित व्यक्तित्वों के विरुद्ध कार्रवाई व सतर्क दृष्टि आदि ने भय व संशयग्रस्त मतदाताओं के अंदर सुरक्षा को लेकर आव्यस्त किया जिससे चुनावी वातावरण में आमूल परिवर्तन आया। भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं

गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पहले दिन से यह विश्वास दिलाने की रणनीति अपनाई कि हम सता में आ रहे हैं तथा किसी के साथ अन्याय हुआ तो पूरी पार्टी खड़ी रहेगी। इन सबका सम्मिलित परिणाम है असंभव सा लगने वाला सत्ता परिवर्तन।

असम में पहले दिन से स्पष्ट था कि वह भाजपा को बड़ी चुनौती नहीं है। किंतु गौरव गोगोई भी जोरहाट से हार जाएँगे इसकी कल्पना कांग्रेस को नहीं रही होगी। राहुल गांधी एवं प्रियंका वाड्रा व उनके रणनीतिकारों के कारण टिकट बंटवारे तक नेता पार्टी छोड़कर जाते रहे। भाजपा ने पिछले लंबे समय



से असम अस्मिता व आसामी संस्कृति को भारत के व्यापक हिंदुत्व संस्कृति और राष्ट्रभाव से जोड़ने में सफलता पाई है। मुगलों से युद्ध करने वाले लचित बरफुकन से लेकर महाराज शंकर देव को जिस तरह भाजपा ने प्रस्तुत किया एवं जनजाति गौरव को निचले स्तर तक ले गए उन सबसे सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ है। सरकार की आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा नीति ने उसे बल दिया है। हिमंता विश्वासरमा की छवि देश में भले घुसपीठी और मुस्लिम विरोधी बनाई गई किंतु इसके साथ असम में उन्होंने बच्चों व युवाओं के मामा और महिलाओं के भाई के रूप में भी छवि बनाई है। असम में घुसपीठी लंबे समय से मुद्दा रहा है और इसके आधार पर वहां 80 के दशक में छत्र नेताओं की सरकार बनी। बाकी पार्टियों ने इसका उपहास उड़ाया और भाजपा आज भी इस पर कायम है। इन सबका असर हुआ है और भाजपा तीसरी बार सत्ता बनाए रखने में कामयाब रही। तमिलनाडु में थलापति विजय की टीवीके या तमिलना वेत्री कल्लमम दोनों मुख्य गठबंधन द्रमुक नेतृत्व आईएनडीआइए तथा अनादमक भाजपा गठबंधन को पड़इ नंबर एक की पार्टी बन जाएगी इसकी कल्पना किसी को नहीं थी। दरअसल, द्रमुक के विरुद्ध सत्ता विरोधी रझान जमीन पर दिख रहा था। इसी कारण एमके स्टालिन ने एक तिहाई विधायकों का टिकट काटा। उन्होंने तमिलवाद और तमिल

# नेचुरल गैस पर बढ़ती निर्भरता और आत्मनिर्भरता का सवाल



**मुद्दा**  
**डॉ. मनीष जैसल**  
लेखक मीडिया शिक्षक हैं।

भारत में ऊर्जा की चर्चा लंबे समय तक पेट्रोएल और डीजल के इंडे-गिर्द घूमती रही, लेकिन पिछले एक दशक में प्राकृतिक गैस एक ईंधन के रूप में तेजी से आम जीवन का हिस्सा बना है। शहरों में बढ़ती सीएनजी गाड़ियों, घरों में पीएनजी से जलते चूल्हे और उद्योगों में इस्तेमाल हो रहे एल एन जी इस बात का संकेत है कि भारत धीरे-धीरे गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। सरकार भी ऊर्जा मिश्रण में गैस की हिस्सेदारी 6-7 प्रतिशत से बढ़कर 15 प्रतिशत तक ले जाने की बात करती रही है। लेकिन इस लक्ष्य के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जिस गैस पर हम अपना भविष्य बना रहे हैं, क्या वह गैस हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है? वास्तविकता यह है कि भारत अपनी जरूरत की बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस आयात करता है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार भारत की गैस खपत लगातार बढ़ रही है, लेकिन घरेलू उत्पादन उसी गति से नहीं बढ़ रहा। 2024 के आसपास के ऊर्जा अंकड़े बताते हैं कि भारत की गैस खपत बढ़ने के साथ एलएनजी आयात भी तेजी से बढ़ा और आयात निर्भरता लगभग 44 प्रतिशत तक पहुँच गई। भारत आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एलएनजी आयातक देश है और पिछले एक दशक में उसके एलएनजी आयात में लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसका अर्थ यह है कि भारत में सीएनजी, पीएनजी और एलएनजी का विस्तार जितनी तेजी से हो रहा है, उतनी ही तेजी से विदेशों पर निर्भरता भी बढ़ रही है।

भारत की स्थिति को समझने के लिए यह भी

देखना होगा कि भविष्य में क्या होने वाला है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अनुमान है कि 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की माँग लगभग 50-60 प्रतिशत तक बढ़ सकती है, जबकि घरेलू उत्पादन बहुत धीमी गति से बढ़ेगा। इसका परिणाम यह होगा कि भारत को एलएनजी आयात को लगभग दोगुना करना पड़ सकता है। यानी यदि नीतियों और उत्पादन में बड़ा बदलाव नहीं हुआ तो भारत गैस के मामले में और अधिक आयात पर निर्भर हो जाएगा। यह स्थिति केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी चिंता का विषय है, क्योंकि ऊर्जा पर निर्भरता हमेशा विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करती है।

अगर हम दुनिया के अन्य देशों से तुलना करें तो भारत की स्थिति और स्पष्ट हो जाती है। अमेरिका आज दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक देश है। वहीं शेल गैस क्रांति के कारण गैस उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हुई और अमेरिका आयातक से निर्यातक देश बन गया। आज अमेरिका एल एन जी निर्यात करके यूरोप और एशिया को गैस बेच रहा है। रूस दुनिया के सबसे बड़े गैस भंडार वाले देशों में है और वह पाइपलाइन के माध्यम से यूरोप और एशिया को गैस भेजता है।

चीन की स्थिति भारत से मिलती-जुलती है, लेकिन उसकी ऊर्जा रणनीति भारत से अधिक मजबूत मानी जाती है। चीन भी एल एन जी आयात करता है, लेकिन उसने घरेलू उत्पादन बढ़ाया, मध्य एशिया और रूस से पाइपलाइन गैस आयात शुरू किया और गैस स्टोरेज की बड़ी क्षमता विकसित की। इस कारण चीन पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं होने के बावजूद ऊर्जा सुरक्षा के मामले में भारत से बेहतर स्थिति में है। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश लगभग पूरी तरह एलएनजी आयात पर निर्भर हैं, लेकिन उन्होंने गैस स्टोरेज, एलएनजी टर्मिनल और सप्लाय सोलॉटों का ऐसा नेटवर्क बनाया है कि ऊर्जा संकट की स्थिति में भी उनकी अर्थव्यवस्था अचानक प्रभावित नहीं होती। जापान कई सप्ताह तक चलने वाला एलएनजी स्टॉक रखता है और कई देशों से गैस खरीदता है। यानी आयात पर निर्भर होने के बावजूद उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर ली है। यूरोप की स्थिति भी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यूरोप लंबे समय तक रूस की गैस पर निर्भर रहा, लेकिन रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद उसने अपनी ऊर्जा नीति बदल दी। उसने नए एलएनजी टर्मिनल बनाए, गैस

सप्लाय के स्रोत बदले और नवीकरणीय ऊर्जा पर निवेश बढ़ाया। अगर इन सभी देशों की तुलना में भारत की स्थिति देखें तो समस्या केवल आयात की नहीं है, बल्कि संरचना की भी है। भारत में गैस पाइपलाइन नेटवर्क अभी भी पूरे देश में नहीं फैला है। कई राज्यों में आज भी पीएनजी उपलब्ध नहीं है। एलएनजी टर्मिनल मुख्य रूप से तटीय क्षेत्रों तक सीमित हैं। गैस स्टोरेज क्षमता बहुत कम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अभी भी अपने एलएनजी आयात के लिए मुख्य रूप से पश्चिम एशिया, विशेषकर कतर, पर निर्भर है। इसका मतलब यह है कि अगर उस क्षेत्र में कोई युद्ध या संकट होता है, तो उसका सीधा असर भारत की गैस सप्लाय और कीमतों पर पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक संकटों के दौरान सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में जो तेजी आई, वह इसी निर्भरता का परिणाम थी। अब प्रश्न यह है कि भारत में गैस उत्पादन क्यों नहीं बढ़ पा रहा। इसका पहला कारण निवेश की स्थिति और स्पष्ट नहीं है और जो है वह समुद्र के गहरे हिस्सों में है, जहाँ से गैस निकालना मरणा और तकनीकी रूप से कठिन है। दूसरा कारण यह है कि भारत में एक्प्लोरेशन यानी तेल और गैस की खोज पर लंबे समय तक पर्याप्त निवेश नहीं हुआ। तीसरा कारण यह है कि गैस की कीमतों पर सरकारी नियंत्रण के कारण निजी कंपनियों बड़े स्तर पर निवेश करने से बचती हैं। चौथा कारण यह है कि गैस पाइपलाइन और वितरण नेटवर्क का विकास दर से शुरू हुआ।

भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या वह गैस में आत्मनिर्भर बन सकता है। इसका उत्तर पूरी तरह ही या नहीं में नहीं दिया जा सकता। भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर शायद नहीं बन पाए, लेकिन आयात निर्भरता को कम जरूर कर सकता है। इसके लिए सबसे पहला काम विशेषकर डीप सी, शेल गैस और कोल बेड मीथेन के क्षेत्र में घरेलू गैस खोज और उत्पादन बढ़ाना होगा। दूसरा, पूरे देश में पाइपलाइन नेटवर्क फैलाना होगा ताकि गैस का उपयोग केवल कुछ शहरों तक सीमित न रहे। तीसरा, एलएनजी आयात के स्रोतों को विविध बनाना होगा ताकि भारत एक ही क्षेत्र पर निर्भर न रहे। चौथा, रणनीतिक गैस भंडार बनाना होगा, जैसे भारत ने तेल के लिए स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया है। पाँचवाँ और सबसे महत्वपूर्ण, भारत को बायोगैस और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे विकल्पों पर तेजी से काम करना होगा, क्योंकि यही ऐसे स्रोत हैं जो भारत में स्थानीय स्तर पर विकसित किए जा सकते हैं। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की

जरूरत है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यह वाक्य हम लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ऊर्जा नीति के संदर्भ में इस वाक्य का वास्तविक अर्थ हमने अभी तक पूरी तरह समझा ही नहीं। प्राकृतिक गैस के संदर्भ में यह बात और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि भारत के पास पारंपरिक गैस भंडार भले सीमित हों, लेकिन जैव-गैस (बायो गैस) और बायो सीएनजी के रूप में गैस उत्पादन की अपार संभावनाएँ मौजूद हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े पशुधन वाले देशों में है, और कृषि अवशेष, गोबर, गन्ने का कचरा, नगरों का जैविक कचरा—ये सभी गैस बनाने के स्रोत हैं। अगर सही नीति के साथ संकट होता है, तो उसका सीधा असर भारत की गैस जरूरत का एक बड़ा हिस्सा खुद पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर साल पराली की समस्या सामने आती है। यहीं पराली बायो सीएनजी का बड़ा स्रोत बन सकता है। कुछ स्थानों पर पराली से बायो सीएनजी बनाकर बसें चलाई जा रही हैं। लेकिन यह अभी बहुत छोटे स्तर पर है। इसी तरह महाराष्ट्र और गुजरात में गन्ने के कचरे से गैस और इथेनॉल बनाने के सफल प्रयोग हुए हैं। अगर देशभर में बड़े स्तर पर बायो सीएनजी प्लांट लगाए जाएँ तो भारत अपनी सीएनजी जरूरत का बड़ा हिस्सा खुद पूरा कर सकता है। दरअसल भारत की ऊर्जा नीति लंबे समय तक शहर और उद्योग केंद्रित रही, गाँव और कृषि की ऊर्जा उत्पादन के स्रोत के रूप में नहीं देखा गया। अगर भारत ने 15-20 वर्ष पहले ही बायोगैस और बायो सीएनजी को राष्ट्रीय ऊर्जा नीति का हिस्सा बना लिया होता, तो आज भारत सीएनजी के लिए विदेशों पर इतनी निर्भरता में नहीं होता। प्राकृतिक गैस का प्रश्न केवल सीएनजी और पीएनजी की कीमत का प्रश्न नहीं है। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और विदेश नीति से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आज भारत अपनी जरूरत की बड़ी मात्रा में गैस आयात करता है और भविष्य में यह निर्भरता और बढ़ सकती है। अगर भारत को वास्तव में आत्मनिर्भर बनना है तो उसे गैस उत्पादन, गैस भंडारण, पाइपलाइन, आयात विविधीकरण और वैकल्पिक गैस स्रोतों पर एक साथ काम करना होगा। जिस देश के पास ऊर्जा है, वही आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत होता है। भारत के सामने आज वही चुनौती है—क्या वह गैस का बड़ा आयातक देश बना रहेगा, या आने वाले वर्षों में वह ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ पाएगा। आने वाले दस वर्ष इस प्रश्न का उत्तर तय करेंगे।



**निर्मल आनंद**  
**रमेश रंजन त्रिपाठी**  
लेखक स्तंभकार हैं।

जो ठ की धूप ने चिलचिलाना शुरू किया उसे बाहर निकलकर सड़कों पर शोर मचाने लगे जैसे पहली बारिश के बाद दादुर टरपने लगते हैं। टंकी, टैंक और टैंकर एक ही परिवार के सदस्यलगतते हैं जिसका टैंक सेना में शामिल हो गया है। मौसम का सबसे ज्यादा फायदा टैंकर उठाता है और अच्छे-अच्छों को पानी पिलाकर पुण्य लुटने लगता है। पैसा तो इस पुण्य का बाई-प्रॉडक्ट है। कुछ लोग इसका उलाहना मारते हैं। वैसे, कीमत वसूल कर किया गया काम व्यापार है या परोपकार? बसस की जरूरत हैक्या? व्यापार और पुण्य एक साथ रह सकते हैं क्या? छोड़िए, ऐसे फालतू सवालों में क्यों उलझना?

ग्रीष्म ऋतु में सबको, यहाँ तक कि सूरज को भी इतनी प्यास लगती हैकि वे पानी के सभी स्रोतों को अपनी ओर खींच लेते हैं। नतीजतन नदियाँ, तालाब दुबले हो जाते हैं जैसे मोटापे की सर्जरी कर ली हो। लेकिन बड़े लोग एहसान नहीं भूलते इसलिए सावन आने पर वे पूरा पानी सूद समेत वापस लौटा देते हैं। प्यासे को पानी पिलाना पुण्यकर्म माना जाता है। मृत पितरों के तर्पण को हिन्दू धर्म में अनिवार्य कर्म की मान्यता है। बीते समय में प्यास बुझाने के लिए पानी मांगने पर साथ में कुछ खाने को भी दिया जाताथा। और कुछ न होने पर गुड़ ही सही। पानी का सबसे बड़ा स्रोत बरसात होती है। नदी, तालाब, पोखर या कुएं का नंबर इसके बाद आता है। कुछ दशक पहले खेतों में सिंचाई के लिए कुओं में मिट्टी के छोटे-छोटे घड़ों से बने रहटको खींचते रहल दिखाई देना आम बात थी। आधुनिक पीछे ने बहल फिल्टर्मोंमें देखा होगा। कोई हैंडपंप, नल, बोरिंग, सीलबंद बोटल को पानी का प्रयुक्त साधन समझने लगे तो ताजुब कैसे? आजकल पानी को फिल्टर करने के लिए हजारों रुपए खर्च किए जाते हैं। महंगे होटलों में खाने के साथ फिल्टर पानी मुफ्तपरसे जोने के बावजूद वेटर पूछा करता है कि सीलबंद बोटल का पानी तो नहीं चाहिए? बहुत से शालक फ्री के शुद्ध जल की बजाय पैसे खर्च कर प्यास बुझाते मिल जाते हैं। एक समय माना जाता था कि बोटल बंद पानी विदेशी लोगोंके लिए है। पता है न कि इन दिनों फिल्टर वाटर न पाने वाले देशी व्यक्ति को क्या कहते हैं? पहाड़ों पर जहाँ जगह-जगह स्वच्छ शीतल जल के झरने बहते हैं,

# पानी रे पानी

लोग वहाँ भी पानी की सीलबंद बोटल लिए मिल जाते हैं।

अदरगज लोगों को आज भी सफर में छगल, सुराही, धर्मस, प्लास्टिक या धातु के बर्तन में पानी लेकर चलना याद है। रेल यात्रियों को स्टेशन परट्रेन के रुकने की अल्प अवधि में भारी धक्कामुक्की के बीच प्लेटफार्म परलगे नल से बोटल में पानी भर लेने के हुनर को सीखना जरूरी होता था। बुजुर्गों ने पिछली सदी में अपनी माताओं को कोएँ, तालाब या नदी से पानी भरकर लाते देखा है। कई जगहों में आज भी पानी के लिए मीलों तक पैसा तो इस पुण्य का बाई-प्रॉडक्ट है। कुछ लोग इसका उलाहना मारते हैं। वैसे, कीमत वसूल कर किया गया काम व्यापार है या परोपकार? बसस की जरूरत हैक्या? व्यापार और पुण्य एक साथ रह सकते हैं क्या? छोड़िए, ऐसे फालतू सवालों में क्यों उलझना?

ग्रीष्म ऋतु में सबको, यहाँ तक कि सूरज को भी इतनी प्यास लगती हैकि वे पानी के सभी स्रोतों को अपनी ओर खींच लेते हैं। नतीजतन नदियाँ, तालाब दुबले हो जाते हैं जैसे मोटापे की सर्जरी कर ली हो। लेकिन बड़े लोग एहसान नहीं भूलते इसलिए सावन आने पर वे पूरा पानी सूद समेत वापस लौटा देते हैं। प्यासे को पानी पिलाना पुण्यकर्म माना जाता है। मृत पितरों के तर्पण को हिन्दू धर्म में अनिवार्य कर्म की मान्यता है। बीते समय में प्यास बुझाने के लिए पानी मांगने पर साथ में कुछ खाने को भी दिया जाताथा। और कुछ न होने पर गुड़ ही सही। पानी का सबसे बड़ा स्रोत बरसात होती है। नदी, तालाब, पोखर या कुएं का नंबर इसके बाद आता है। कुछ दशक पहले खेतों में सिंचाई के लिए कुओं में मिट्टी के छोटे-छोटे घड़ों से बने रहटको खींचते रहल दिखाई देना आम बात थी। आधुनिक पीछे ने बहल फिल्टर्मोंमें देखा होगा। कोई हैंडपंप, नल, बोरिंग, सीलबंद बोटल को पानी का प्रयुक्त साधन समझने लगे तो ताजुब कैसे? आजकल पानी को फिल्टर करने के लिए हजारों रुपए खर्च किए जाते हैं। महंगे होटलों में खाने के साथ फिल्टर पानी मुफ्तपरसे जोने के बावजूद वेटर पूछा करता है कि सीलबंद बोटल का पानी तो नहीं चाहिए? बहुत से शालक फ्री के शुद्ध जल की बजाय पैसे खर्च कर प्यास बुझाते मिल जाते हैं। एक समय माना जाता था कि बोटल बंद पानी विदेशी लोगोंके लिए है। पता है न कि इन दिनों फिल्टर वाटर न पाने वाले देशी व्यक्ति को क्या कहते हैं? पहाड़ों पर जहाँ जगह-जगह स्वच्छ शीतल जल के झरने बहते हैं,

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पंकज प्रिंटर्स एंड पैकेजिंग, 16, अल्हा इंडस्ट्रियल पार्क, जाखिया, इंदौर, म.प्र., 453555 से मुद्रित एवं 6612, साई कृपा कॉलोनी, बाँबे हाँस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

**प्रधान संपादक**  
उमेश त्रिवेदी

**कार्यकारी प्रधान संपादक**  
अजय बोक्लि

**संपादक (मध्यप्रदेश)**  
विनोद तिवारी

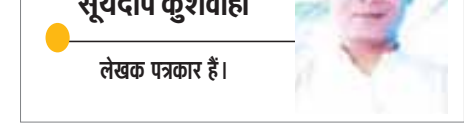
**स्थानीय संपादक**  
हेमंत पाल

**प्रबंध संपादक**  
रमेश रंजन त्रिपाठी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)  
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,  
Mobile No.: 09893032101  
Email- subahsaverenews@gmail.com

**‘सुबह सवेरे’ में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनके समावाहक पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।**

## खंगर



**सूर्यदीप कुशवाहा**  
लेखक पत्रकार हैं।

आज कलयुग में अगर आप किसी से कहें कि झूठ बोलना पाप है, तो वह आपको महान नहीं बल्कि मुर्ख समझेगा। यह कहवात तो आपने सुनी ही होगी कि झूठ बोले कौवा काटे। आज के जमाने में कौवे भी लौंडे इतने बेरोजगार हो चुके हैं कि उन्होंने काटना छोड़कर सोशल मीडिया पर कांव-कांव करना बेहतर समझा है। रही बात झूठ से मुँह काला होने की, तो आज के डिजिटल युग में मुँह का लाला नहीं होता, बल्कि उसे फिल्टर से इतना चमका दिया जाता है कि झूठ भी सच से ज्यादा हसीन लगने लगता है। प्राचीन काल में शायद

## झूठ बोले कौआ भी न काटे

मुँह काला करने की परंपरा रही होगी ताकि समाज को पता चल सके कि यह व्यक्ति झूठ है। लेकिन आज? आज तो झूठ एक अनिवार्य योग्यता बन चुका है। अगर आपके पास सफेद झूठ बोलने की कला है, तो आप राजनीति से लेकर मार्केटिंग तक और ऑफिस की मीटिंग से लेकर शादी के बायोडाटा तक, कहीं भी जीते के झंडे गाड़ सकते हैं। अब मुँह काला करने के लिए कालिख नहीं मिलती, क्योंकि सारी कालिख तो उन चुनावी वादों पर ही है जो कभी पूरे नहीं होते।कल्पना कीजिए, अगर आज के दौर में सचमुच झूठ बोलने पर मुँह काला होने लगता, तो नजारा क्या होता! सुबह का अखबार बेचने वाला, टीवी पर चिल्लाता चंकर, और चुनाव से पहले हाथ जोड़ता नेता... सबके चेहरे ऐसे काले होते कि

## पहचानना मुश्किल हो जाता कि ये ईसान है या रात के डारवने साए।

फेरनेस क्रोम बनाने वाली कंपनियाँ दिवालिया हो जातीं और फेंस वॉश की जगह अस्सी चारकोल की माँग बढ़ जाती। विडंबना देखिए, आज हम उस समाज में रह रहे हैं जहाँ सच बोलने वाले को बेवकूफ कहा जाता है और सफाई से झूठ बोलने वाले को स्मार्ट बूंद जोकि नंगा है। जो जितना बड़ा झूठ है, उसका मुँह उतना ही उज्ज्वल है। लोग अब मुँह पर कालिख लगने से नहीं डरते, वे बस इस बात से डरते हैं कि कहीं उनका झूठ नरक का राजा न बना दे। डिजिटल युग में मुँह काला होना अब ब्लॉक होने या ट्रेंड में आने के बराबर है।झूठ अब केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहा। यह हमारे पहनावे, हमारे स्टेटस और हमारी मुस्कुराहटों में

## भी घुस गया है। हम खुश होने का झूठ बोलते हैं, हम व्यस्त होने का झूठ बोलते हैं, और हम सबसे बड़ा झूठ तो खुद से बोलते हैं कि सब ठीक है। असल में, झूठे का मुँह काला...ऐसी चेतावनी बन गई है जिसे हमने रद्दी की टोकरी में डाल दिया है।इसका सार यही है कि जिस दिन कालिख की कीमत बढ़ जाएगी और झूठ बोलने वालों के चेहरे सचमुच काले होने लगेंगे, उस दिन दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। क्योंकि तब प्रकाश फैलाने वाले चेहरे बहुत कम बचेंगे। फिलहाल तो स्थिति यह है कि झूठ की चमक इतनी ज्यादा है कि सच अपनी आँखों पर काला चश्मा लगाए कोने में बैठ अपनी बारी का इंतजार कर रहा है।झूठयुग कब समाप्त होगा और सचयुग का आरंभ होगा... क्योंकि अभी झूठ बोले कौआ भी न काटे।

# समरसता, भक्ति और सामाजिक चेतना के आद्य प्रवर्तक

**काल महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के विस्तार का समय था। तत्कालीन समय में अनुसूचित जाति को सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्तर पर अनेक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता था। मंदिर प्रवेश, शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में उन्हें स्थान नहीं था। ऐसी विषम सामाजिक परिस्थितियों में संत चोखामेला का उदय हुआ। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से यह संदेश दिया कि ईश्वर सबका है। उनके हृदय में विट्ठलभक्ति की अखंड धारा प्रवाहित होती थी। वे पंढरपुर के भगवान विट्ठल (भगवान श्री कृष्ण) के अनन्य भक्त थे।**



संत चोखामेला

गिरीश जोशी

संस्कृति अध्येता एवं स्तंभकार

महाराष्ट्र की वारकरी परंपरा में संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम आदि के साथ-साथ संत चोखामेला का स्थान बहुत बढ़ा है। उन्होंने अपने जीवनानुभवों के माध्यम से भेदभाव की पीड़ा को शब्द दिए और भक्ति मार्ग से समरसता का संदेश दिया।

मराठी संत साहित्य में संत चोखामेला को अत्यंत तेजस्वी, करुणामय और क्रांतिकारी व्यक्तित्व का कलमकार माना जाता है। वारकरी संप्रदाय के वे ऐसे संत थे जिन्होंने भक्ति के माध्यम से सामाजिक समानता का संदेश दिया। उनके अर्भगों में ईश्वर भक्ति, मानवीय पीड़ा, भेदभाव का विरोध और भगवान विट्ठल के प्रति अखंड प्रेम दिखाई देता है। संत चोखामेला केवल संत कवि ही नहीं थे, बल्कि वे अनुसूचित जाति समाज की चेतना को आवाज देने वाले आद्य प्रवर्तक भी माने जाते हैं। संत चोखामेला मराठी के पहले अनुसूचित जाति समाज के संतकवि माने जाते हैं। उनके अर्भगों में स्वतंत्र सामाजिक वेदना केवल व्यक्तित्व नहीं, बल्कि सामूहिक इतिहास की साक्षी है। उन्होंने ईश्वर भक्ति के माध्यम से समाज सुधार का मार्ग दिखाया।

## पृष्ठभूमि

संत चोखामेला का जन्मकाल लगभग 13वीं-14वीं शताब्दी माना जाता है। उनका जन्म महार समाज में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम सोयराबाई था, जो स्वयं भी भक्त कवयित्री थीं। उनके पुत्र कर्मा मेला का भी संत परंपरा में उल्लेख मिलता है।

ये काल महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के विस्तार का समय था। तत्कालीन समय में अनुसूचित जाति को सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्तर पर अनेक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता था। मंदिर प्रवेश, शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में उन्हें स्थान नहीं था। ऐसी विषम सामाजिक परिस्थितियों में संत चोखामेला का उदय हुआ। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से यह संदेश दिया कि ईश्वर सबका है। उनके हृदय में विट्ठल भक्ति की अखंड धारा प्रवाहित होती थी। वे पंढरपुर के भगवान विट्ठल (भगवान श्री कृष्ण) के अनन्य भक्त थे।

## संत नामदेव का सत्संग

संत चोखामेला को संत नामदेव का सान्निध्य प्राप्त हुआ। नामदेव की संगति में उनकी भक्ति को अधिक परिपक्व दिशा मिली। वारकरी परंपरा के समानता, प्रेम, नामस्मरण और ईश्वर से सीधे संबंध जैसे विचारों का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। संत नामदेव और वारकरी संप्रदाय की परंपरा के संतो ने भक्ति को जातिभेद से परे सार्वभौमिक साधना माना। यही

विचार चोखामेला के अर्भगों में स्पष्ट दिखाई देता है। संत नामदेव की संगति में उनकी भक्ति और दृढ़ हुई तथा उन्होंने विट्ठल भक्ति अपने भावों को स्वर देने के लिए अभंग रचकर समाज के अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई और समरसता स्थापित करने की पहल की।

## पंढरपुर से संबंध

चोखामेला आगे चलकर पंढरपुर आए और विट्ठल भक्ति में लीन हो गए। मंदिर में प्रवेश निषिद्ध होने पर भी वे मंदिर के बाहर खड़े होकर भगवान विट्ठल का नाम स्मरण और संकीर्तन करते थे। लोक श्रुति है कि स्वयं भगवान विट्ठल मंदिर के गर्भगृह से बाहर आकर उन्हें दर्शन देते थे।

## प्रमुख उपलब्धियाँ

- भेदभाव के विरुद्ध आवाज** - उनके अर्भगों में समाज की विषमता और भेदभाव पर प्रखर प्रहार दिखाई देता है। उन्होंने विद्रोह किया, परंतु कटुता से नहीं, बल्कि करुणा और भक्ति के मार्ग से।
- वारकरी संप्रदाय का प्रसार** - वारी, नामस्मरण और अभंग लेखन तथा गायन के माध्यम से उन्होंने सामान्य जन तक भक्ति का संदेश पहुँचाया।
- आत्मसम्मान की प्रेरणा** - उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व से अनुसूचित और वंचित समाज को आत्मबोध और स्वाभिमान की प्रेरणा मिली।

## अर्भगों की विशेषताएँ

संत चोखामेला ने भगवान विट्ठल कि भक्ति में अनेक अर्भगों (मराठी भजनों) की रचना की। आपके भाषा अत्यंत सरल, सहज और लोकभाषा की शैली में होती थी। आपने अपने अर्भगों से सामाजिक चेतना जगाने का काम किया। आपके अर्भगों में भक्ति और विद्रोह का अनूठा संगम दिखाई



देता था। आपके अर्भगों में आत्मानुभव प्रमुख रूप से प्रगट हुआ है। आपने अपनी भक्तिमय रचनाओं से समरसता का सार्वकालिक संदेश दिया। आपके संदेश में सामाजिक क्रांति का प्रखर तेज झलकता रहा।

## प्रसिद्ध अर्भग

संत चोखामेला ने अनेक अर्भग लिखे हैं। उनका लिखा एक अर्भग अत्यंत लोकप्रिय है।  
 'ऊस डोंगा परी रस नव्हे डोंगा। काय भुललासी वरलिया रंगा ॥1॥

कमान डोंगी परी तीर नोहे डोंगा। काय भुललासी वरलिया रंगा ॥2॥

नदी डोंगी परी जळ नव्हे डोंगें। काय भुललासी वरलिया रंगा ॥3॥

चोखा डोंगा परी भाव नव्हे डोंगा। काय भुललासी वरलिया रंगा ॥4॥

अर्थ : किसी के बाहरी स्वरूप देखकर ध्रमिंत नहीं होना चाहिए। गन्ना टढ़ा होता है, पर उसका रस मीठा होता है। धनुष की कमान टढ़ी होती है लेकिन तीर टढ़ा नहीं होता। नदी टढ़ी - मेड़ी होती है लेकिन जल टढ़ा मेड़ा नहीं होता। चोखामेला का रंग रूप जो कुछ भी हो लेकिन उसका भक्ति भाव टढ़ा नहीं है। इस अर्भग का भाव ये है कि मनुष्य का मूल्य जाति या रूप से नहीं बल्कि गुणों से होता है। हमारा बाहरी रंग - रूप, हमारी पहचान जो कुछ भी हो लेकिन भीतर जो है उसका बाहरी पहचान से कोई संबंध नहीं है, वह तो सबके भीतर एक समान, शुद्ध, निर्मल और आनंद मय स्वरूप है।

संत चोखामेला मन में किसी प्रकार का पूर्वाग्रह या दुराग्रह रख कर प्रतिकार करने में विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि उन्होंने अपनी विट्ठल भक्ति को ही प्रतिरोध का साधन बना लिया था। मंदिर के बाहर खड़ा यह संत वास्तव में संपूर्ण व्यवस्था से प्रश्न करता है, जो मन से निर्मल है, शुद्ध है, वह ईश्वर दर्शन से वंचित क्यों रहे ?

## साहित्य में महत्व

अनुसूचित समाज के साहित्य के उदय से पहले ही चोखामेला ने अनुसूचित समाज के अनुभव को स्वर दिया। इसलिए अनेक विद्वान उन्हें अनुसूचित समाज के साहित्य का आद्य स्वर मानते हैं। उनके काव्य की पीड़ा व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक है। संत चोखामेला केवल भक्तकवि नहीं थे, बल्कि सामाजिक आत्मजागरण के विचारक संत थे। उन्होंने भेदभाव की वेदना को भक्ति की भाषा दी। उनके अर्भग केवल भक्ति गीत नहीं, बल्कि समाज जागरण के दस्तावेज



मैं हूँ ना

सुधीर कुमार सोनी

लेखक साहित्यकार हैं।

बहुत दिनों से मेरे मित्र अख्तर का फोन नहीं आया था, मैं भी अपने व्यवसाय की व्यस्तता के कारण उससे मोबाइल से बात नहीं कर पाया था। पचपन साल की दोस्ती में हम लगातार संपर्क में हैं। हमने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई साथ में पूरी की थी। स्कूल से भागकर हम फिल्म में भी देखने जाते थे। कुछ वर्षों से हम चार दोस्त छत्रीसगढ़ के आसपास के पर्यटन स्थलों को देखने महीने दो महीने के अंतराल में जा रहे थे। रविवार की शाम तय ही था कि मिलना है। मैंने सुबह साढ़े आठ बजे मोबाइल लगाया। 'हलो क्या हाल है ?

'बस यार कुछ दिनों से मन अस्थिर सा है' अख्तर ने जवाब दिया।

'तुमने भी बात नहीं की बहुत दिनों से, मैं भी व्यस्तता के कारण फोन नहीं लगा पाया' मैंने कहा

'हाँ यार बहुत दिनों से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। नकारात्मक सोच दिमाग में घुसे थी। ऐसा लग रहा है कि जीने की इच्छा ही नहीं रही' अख्तर ने कहा।

'ऐसा क्या हो गया जो तुम इस तरह सोचने लगे। तुम तो रोज ही लिखने में व्यस्त रहते हो। यह सोच तो खाली बैठे लोगों का है'

'थोड़ी तबियत ठीक नहीं थी, हल्का बुखार था। दो

दिन से दुकान भी नहीं खोला। बस आराम ही किया तो सारी नकारात्मकता ने ही मस्तिष्क में घर बना लिया, जैसे वहन जाने कब से मेरे मस्तिष्क में घुसने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हम लोग भी बहुत दिनों से मिले भी नहीं हैं। दो दिन रविवार भी निकल गए।'

'चलो, आज दिन में आता हूँ मैं' इतना कहकर मैंने मोबाइल टेबल पर रखा। मुझे उससे बात करने में लगा जैसे उसके भीतर चरमराकर कुछ टूट रहा है और जिसकी आवाज उसे बचने कर रही है। हम काफ़ी दिनों से आपस में नहीं मिले पाए थे। मित्रों को मिलते रहना चाहिए, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें व्यक्ति मित्रों से ही साझा करना चाहता है। लेकिन उस के इस पड़ाव में हमें अपने मित्रों से मिलने जाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सड़क में इतना ट्रैफिक है कि हमें गाड़ी चलाने में बहुत डर लगता है। नये लड़के बेतरतीब ढंग से चलते हैं और दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं। मैं ब्रश और टॉवल लेकर नहाने के लिए बाथरूम चला गया। नहाना कर लिया और दुकान खोल ली, तब तक ग्यारह बजे चुके थे। बेटा दुकान के काम से बाहर गया था। तब तक मैं दुकान की डायरी देखने लगा कि क्या क्या किसका ऑर्डर है जिसे पूरा करना है। थोड़ी देर बाद मैंने डायरी रख दी। बोलात से पानी पी कर रखा तो ध्यान आया कि नकारात्मक तो भी सोचता रहता हूँ। किसी अप्रिय घटना भी के कारण भी

# धूप में छायादार वृक्ष की तरह होना

नकारात्मक सोच मस्तिष्क में आ जाते हैं। मैं सोच में डूबा था तभी बेटा आ गया।  
 'तैयार होकर जल्दी आना मुझे काम से जाना है' मैंने बेटे से कहा-  
 'ठीक है, लेकिन एक काम मुझे पूरा करना है। एक घंटे लग जायेंगे' बेटे ने कहा और ऊपर घर चला गया।  
 डेढ़ घंटे बाद बेटा तैयार होकर दुकान आया तो मैंने अपनी गाड़ी निकाली और अख्तर के घर के लिए निकल पड़ा। पंद्रह मिनट बाद मैं अख्तर के घर के सामने था। मैंने घंटी बजायी। दरवाजा अख्तर ने ही खोला।

'आओ, अंदर आओ' अख्तर ने कहा। मैं अंदर जाकर सोफे में बैठ में बैठ गया। अख्तर ने भाभी को आवाज दी 'आमना पानी लेकर आना' थोड़ी देर में भाभी पानी लेकर आ गयी। 'भैया चाय पीयेंगे ना'  
 'नहीं भाभी अभी घर से पीकर आ रहा हूँ। सुबह दो तीन चाय हो जाती है'  
 थोड़ी देर यूँ ही बैठने के बाद मैंने कहा 'आखिर क्या बात हो गयी जो तुम सटपटग सोचने लगे'  
 'पता नहीं यार, मुझे लगता है आदमी को व्यस्त रहना चाहिए। खाली बैठना अच्छा नहीं होता है। नकारात्मक चीजें रास्ता देखती रहती हैं कि कब आदमी खाली हो और वह उसके मस्तिष्क में कब्जा

कर ले। हालाँकि कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है लेकिन पहली बार उस ने बता दिया कि भीतर कुछ मरम्मत की आवश्यकता है' अख्तर थोड़ी देर चुप रहा फिर बोला 'ऐसा लगता था मानो मेरे भीतर कोई पहाड़ दरक रहा है, जिसकी आवाज को सिर्फ मैं ही सुन सकता हूँ।'

'मैं भी कभी कभी इस तरह सोचता हूँ, लेकिन बहुत गंभीरता से नहीं लेता। तुमने बहुत भावुक होकर अपने भीतर नकारात्मक चीजों को उतार लिया है' मैंने कहा।

'अख्तर, कहाँ हो' बाहर दरवाजे पर किसी ने आवाज लगायी। मुझे लगा शायद अख्तर के बड़े भाई को आवाज थी।

'आओ भाई' कहकर अख्तर ने दरवाजा खोला और बड़े भैया अंदर आ गये।  
 'भैया नमस्कार'  
 'और कैसे हो सुधीर'  
 'आपकी दुआ है भैया' मैंने कहा  
 सोफे पर बैठते हुए बड़े भाई ने कहा 'क्या हुआ है तुमको, सारी बहनों ने मुझे बार बार फोन किया है कि आप अख्तर का हालचाल पूछने नहीं गये हो' बड़े भाई ने अख्तर और मुझे संबोधित करते हुए कहा।  
 'दो दिन हल्का बुखार था तो आराम ही किया। सोये-सोये बहुत सारी अनावश्यक बातें दिमाग में आती गयीं। कहीं कुछ हो गया तो क्या होगा। बार बार

एक ही बात दिमाग में घूमती रही' अख्तर ने अपने बड़े भाई को अपनी परेशानी बतायी। बात करते हुए ऐसा लगा किसी छलपटहाट से वह मुक्ति पाना चाहता है।

'देखो अख्तर जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरी साँसें जब तक चल रही हैं मैं तुमको कुछ नहीं होने दूँगा। मेरा पास जो भी है, पाई पाई खर्चा हो जाए, अपने आखिरी साँस तक तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। कितनी भी परेशानी आ जाए मैं हूँ ना, मेरे रहते किसी बात की चिंता मत करना।'

बड़े भाई के इतना कहते ही अख्तर के आँख से आँसुओं की धार बह निकली और वह खड़े होकर अपने बड़े भाई से लिपट गया।

'भाई अब अम्मा-अम्मा तो रहें नहीं, जो कुछ है अब आप ही हैं। आपके इतना भर कह देने से कि मैं हूँ ना मेरी सारी परेशानियों को आपने दूर कर दिया। मैं तो आपके बेटा के ही जैसा हूँ। आप जब कॉलेज पढ़ते तो मेरा जन्म हुआ था' थोड़ी देर बाद बड़े भाई से अख्तर अलग हुआ और सोफे में बैठ गया। मेरी भी आँखें भर आयी थीं। इस दृश्य को देखकर इस वर्तमान समय में जब भाई भाई का दुश्मन है तब भरत मिलाप जैसा दृश्य ने मेरी आँखों में पानी ला दिया था।

थोड़ी देर में भाभी ने चाय लाकर रखा। हम तीनों ने चाय पी।

'अब आप दोनों बैठिए मैं चलता हूँ, कुछ जरूरी काम है' इतना कहकर मैंने अपनी गाड़ी चालू की और

हैं। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर सबका है, मनुष्य की श्रेष्ठता जात- पात में नहीं, भक्ति और मानवता में है।

## वारकरी संप्रदाय में स्थान

वारकरी परंपरा में संत चोखामेला समरसता के प्रतीक माने जाते हैं। पंढरपुर मंदिर के सामने उनकी समाधि है। वारकरी आज भी पहले चोखोबा को प्रणाम करते हैं फिर भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए मंदिर में जाते हैं। ये प्रणाम लोकमानस में उनके प्रति सर्वोच्च सम्मान और श्रद्धा का प्रमाण है। संत चोखामेला उस धारा के प्रवर्तक हैं जिन्होंने अनेक प्रकार के भेदभाव को सहन करके भी अपने भीतर की सकारात्मकता, अनन्य भक्ति - भाव और ईश्वर के प्रति श्रद्धा को नहीं छोड़ा। इसीलिए उनको पंढरपुर में संतों की मालिका में वह स्थान मिला जो बिरलों को ही मिलता है। आज भी उनके द्वारा भगवान विट्ठल की भक्ति में रचे गए अभंग सभी समाज के लोग उतनी ही श्रद्धा से और भक्ति भाव से गाते हैं।

## वास्तव में संत चोखामेला जैसी

महान विभूतियों ने ये संदेश दिया है कि किसी काल - परिस्थिति में समाज में विभेद खड़े हुए, कोई एक समाज मुख्य धारा से वंचित रहा, उपेक्षित रहलेकिन ये दायित्व पूरे समाज का है कि वह किसी प्रकार की श्रेष्ठ अथवा हीनता की भावना का बोध आगे लेकर ना चले, अन्याथा समाज के भीतर व्याप्त भेदभाव मिट नहीं पाएगा। वे इस विचार के प्रबल समर्थक थे कि भेदभाव को कटुता से नहीं मिटाया जा सकता वरन आपस में प्रेम - समन्यय और संवाद से ही इसे दूर करके मिटाया जा सकता है।

ऐसा कहा जाता है कि जब पंढरपुर मंदिर के परकोटे का निर्माण कार्य चल रहा था तब उनके ऊपर एक दीवार गिरने से उनका निधन हुआ। लोककथा है कि अंतिम संस्कार के बाद भी उनकी अस्थियों से भी 'विट्ठल, विट्ठल' की ध्वनि सुनाई देती रही। यह उनकी अखंड भक्ति, जिजीविषा और समर्पण का प्रतीक है।



स्वीन्द्रनाथ टैगोर जयंती पर विशेष

श्वेता गोयल

लेखक शिक्षक हैं।

कलकत्ता की तंग गलियों से निकलकर विश्व की वैचारिक वीथिकाओं तक जिस एकव्यक्तित्व ने भारतीय मनीषा की सुगंध बिखेरी, वे थे गुरुदेव स्वीन्द्रनाथ टैगोर। 7 मई 1861 की तिथि भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण के उस सूर्य का उदय था, जिसने पराधीनता के अंधकार में डूबी एक कौम को आत्म-सम्मान और वैश्विक दृष्टि का पाथेय दिया। टैगोर केवल एक साहित्यकार नहीं थे बल्कि एक ऐसी अलौकिक अभिव्यक्ति थे, जिसमें संगीत की लय, कविता की गहराई, दर्शन की ऊंचाई और चित्रकला की निगूढ़ता का एक साथ संगम होता था। उनका व्यक्तित्व हिमालय का विशाल और गंगा की धारा सा पवित्र था, जिसमें भारत की मिट्टी की सौंधी महक भी थी और उपनिषदों का वह शाश्वत सत्य भी, जो संपूर्ण चराचर जगत को एक सूत्र में पिरोने का सामर्थ्य रखता है।

जब हम टैगोर के सुजन संसार में प्रवेश करते हैं तो पाते हैं कि उनकी कलम ने केवल शब्दों को कागज पर नहीं उकेरा बल्कि भारत के 'आत्मा-संगीत' की रचना की। उनका साहित्य एक विशाल वटवृक्ष की भांति है, जिसकी शाखाएँ दर्शन, राजनीति, समाजशास्त्र और कला के विभिन्न आयामों तक फैली हुई हैं। टैगोर उस समय के मनोर्षी थे, जब भारत अपनी पहचान की तलाश में छटपटा रहा था। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से यह सिद्ध किया कि राष्ट्रवाद का अर्थ केवल सीमाओं की रक्षा नहीं, अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़कर वैश्विक मानवता का आलिंगन करना है। उनकी 'गीतांजलि' के स्वर जब विश्व पटल पर गुंजे तो पारंपार्य जात स्वस्थ रह गया। वह पहली बार था कि पूर्व की किसी आवाज ने पश्चिम के भौतिकवादी शोर को शांत कर उसे

# मानवता के महाप्राण और वैश्विक चेतना के शिल्पी टैगोर

**कोरी भावुकता से राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने 'शांतिनिकेतन' के रूप में एक ऐसे शैक्षिक स्वान को साकार किया, जहां प्रकृति के सानिध्य में मनुष्य की अंतरात्मा का विकास हो सके। उनके लिए शिक्षा चारदीवारी और किताबी ज्ञान का नाम नहीं था बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया थी, जो मनुष्य को प्रकृति और परिवेश के साथ एकाकार कर दे। शांतिनिकेतन में उन्होंने जिस 'विश्वभारती' की संकल्पना की, उसका मूल मंत्र ही था, 'यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्' अर्थात् जहां सारा विश्व एक नीड़ (घोंसला) बन जाता है। इसी वैश्विक बोध के कारण उन्होंने संकुचित राष्ट्रवाद की कड़े शब्दों में आलोचना की। उनका स्पष्ट मानना था कि यदि राष्ट्रवाद मानवता की बलि चढ़ाने लगे तो वह एक हिंसक और विनाशकारी शक्ति बन जाता है।**

आध्यात्मिकता और प्रेम के मर्म से परिचित कराया था। नोबेल पुरस्कार तो केवल उस प्रतिभा की एक औपचारिक स्वीकृति भर थी अन्यथा टैगोर का कद तो उन पुरस्कारों की परिधि से कहीं ऊंचा था।

टैगोर की सबसे बड़ी विशेषता उनकी समन्वयकारी दृष्टि थी। वे जानते थे कि कोरी भावुकता से राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने 'शांतिनिकेतन' के रूप में एक ऐसे शैक्षिक स्वप्न को साकार किया, जहां प्रकृति के सानिध्य में मनुष्य की अंतरात्मा का विकास हो सके। उनके लिए शिक्षा चारदीवारी और किताबी ज्ञान का नाम नहीं था बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया थी, जो मनुष्य को प्रकृति और परिवेश के साथ एकाकार कर दे। शांतिनिकेतन में उन्होंने जिस 'विश्वभारती' की संकल्पना की, उसका मूल मंत्र ही था, 'यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्' अर्थात् जहां सारा विश्व एक नीड़ (घोंसला) बन जाता है। इसी वैश्विक बोध के कारण उन्होंने संकुचित राष्ट्रवाद की कड़े शब्दों में आलोचना की। उनका स्पष्ट मानना था कि यदि राष्ट्रवाद मानवता की बलि चढ़ाने लगे तो वह एक हिंसक और विनाशकारी शक्ति बन जाता है। वे एक ऐसे भारत का स्वरण देखते रहे, जहां चित्त भयमुक्त हो और मस्तक गौरव से ऊंचा रहे। उनका राष्ट्रवात 'जन गण मन' इसी विपट चेतना का प्रतिबिंब है, जिसमें भारत की भौगोलिक

विविधता और सांस्कृतिक एकता का अद्भुत सामंजस्य है।

टैगोर के उपन्यासों और कहानियों की बात करें तो उनमें समाज के अंतिम व्यक्ति की वेदना और मध्यम वर्ग के अंतर्द्वंद्व का सजीव चित्रण मिलता है। 'गोरा' में जहां वे धर्म और राष्ट्रवाद की रूढ़ियों पर प्रहार करते हैं, वहीं 'घरे-बाहरे' के माध्यम से स्त्री की स्वतंत्रता और उसके अंतर्मन की जटिलताओं को बड़ी बारीकी से उकेरते हैं। 'कालुचीवाला' जैसी कहानियां यह बताती हैं कि पिता का वास्तव्य और मनुष्य का प्रेम किसी भौगोलिक सीमा या राष्ट्रीयता का मोहताज नहीं होता। टैगोर की दृष्टि में नारी केवल करुणाकी मूर्ति नहीं थी बल्कि वह एक तार्किक और संवेदनशील व्यक्तित्व थी, जो समाज के रूढ़िवादी ढंके को चुनौती देने का साहस रखती थी। उनकी रचनाओं में 'बिनोदिनी' से लेकर 'चारुलता' तक के चरित्र आज भी उतने ही प्रासंगिक और जीवंत जान पड़ते हैं, जितने वे दशकों पहले थे।

संगीत के क्षेत्र में टैगोर ने 'स्वीन्द्र संगीत' की एक ऐसी धारा प्रवाहित की, जो शास्त्रीय संगीत की मर्यादा और लोक संगीत की सरलता का अद्भुतसम्मिश्रण है। उनके दो गीतों के अतिरिक्त गीत प्रकृति के बदलते रंगों, उनमें की निगूढ़ अनुभूतियों और ईश्वर के प्रति अटूट समर्पण की गाथा सुनाते हैं। टैगोर का संगीत केवल

कानों को सुख देने वाला नहीं है बल्कि आत्मा को झुंझूट करने वाला एक आध्यात्मिक अनुभव है। दिलचस्प तथ्य यह है कि वे विश्वके एकमात्र ऐसे रचनाकार हैं, जिनकी कृतियां तीन देशों (भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका) के राष्ट्रपान की आधारशिला बनीं। यह उनके सुजन की व्यापकता और स्वीकार्यता का सबसे बड़ा प्रमाण है। उनके शब्द और धुनें केवल बंगाल या भारत तक सीमित नहीं रही बल्कि उन्होंने समूचे दक्षिण एशिया की चेतना को प्रभावित किया। टैगोर एक ऐसे योद्धा भी थे, जिन्होंने अन्याय के विरुद्ध सहैव अपनी आवाज बुलंद की। जलियांवाला बाग के भीषण नरसंहार ने जब देश की आत्मा कोलहलुलुहान कर दिया, तब टैगोर ने अपनी 'नाइटहुड' की उपाधि को ब्रिटिश हुकुमत के मुंह पर दे मारा। उनका वह पत्र, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'सम्मान के ये तमगे अपमान के इस संदर्भ में निलंबन की तरह चुप रहे हैं', भारतीय स्वाभिमान के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। वे महात्मा गांधी के साथ वैचारिक मतभेद रखते हुए भी उनके प्रति अगाध श्रद्धा रखते थे। गांधीजी को 'महात्मा' की उपाधि देना और स्वयं गांधीजी द्वारा उन्हें 'गुरुदेव' पुकारना, दो महान आत्माओं के बीच के उस आदर को दर्शाता है, जो आज के दौर में दुर्लभ है। टैगोर की राजनीति सत्ता की राजनीति नहीं थी, वह मूल्यों की

राजनीति थी। वे बंगाल विभाजन के समय सड़कों पर उतर आए और 'राखी' को भाईचारे का प्रतीक बनाकर साम्प्रदायिक सौहार्द की एक नई इबारतलिखीं। जीवन के सांध्यकाल में जब अधिकांश लोग विश्राम की खोज करते हैं, टैगोर नेतृलिका थाम ली। उनकी चित्रकला किसी पारंपरिक स्कूल की मोहताज नहीं थी। उनके चित्रों में जो रेखाएं और रंग उभरे, वे उनके अवचेतन की अभिव्यक्ति थे। उनमें एक अजीब सी रहस्यमयी बेचैनी और आधुनिकता थी, जो यह बताती थी कि टैगोर का कलाकार कभी बूढ़ा नहीं हुआ। वे निरंतर प्रयोगधर्मी बने रहे। उनकीकला में वही सरलता थी, जो उनके व्यक्तित्व में थी, बिना किसी दिखावे के, सत्य के साथ साक्षात् साक्षात्कार। टैगोर का दर्शन हमें सिखाता है कि सत्यकेवल तथ्यों का संकलन नहीं है बल्कि वह अनुभूतियों का विस्तार है। उन्होंने जिस 'सत्यम शिवम सुंदरम' की व्याख्या की, वह उनके जीवन के प्रत्येक कृत्य में परिलक्षित होती थी। वे मानते थे कि ईश्वर केवलमंदिरों और मस्जिदों में नहीं रहता, बल्कि वह उस किसान के साथ है, जो कड़ीधूप में हल चला रहा है और उस मजदूर के साथ है, जो पत्थर तोड़ रहा है। आजके दौर में, जब दुनिया वैचारिक संकीर्णता, धार्मिक कट्टरता और पंथवादी संकट से जुझ रही है, टैगोर के विचार एक प्रकाश स्तंभ की तरह

प्रतीतहोते हैं। प्रकृति के साथ मनुष्य का क्या संबंध होना चाहिए, यह टैगोर सेबेहतर कोई नहीं समझ सकता था।

स्वीन्द्रनाथ टैगोर ने जिस 'स्वदेशी समाज' की कल्पना की थी, वह आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का समाज था। उन्होंने कृषि सुधारों, ग्रामीणउत्थान और सहकारिता के क्षेत्र में जो कार्य शांतिनिकेतन के आसपास किए, वे आज के विकास मॉडलों के लिए भी मार्गदर्शक हो सकते हैं। वे एक ऐसेस्वप्नद्रष्टा थे, जिन्होंने अतीत के गौरव और स्वतंत्रता की चाह जीवित रहीं, टैगोर अपनी रचनाओं के माध्यम से हमारे बीच जीवित रहीं। वे आज भी अपनी पंक्तियों के माध्यम से हमें पुकार रहे हैं कि हम उस उजाले की ओर बढ़ें, जहां सत्य की सत्ता हो और मनुष्य का मनुष्य से प्रेम ही एकमात्र धर्म हो।

## विधायक ट्राफी विजेता को मिलेंगे 81 हजार, आठवें दिन विश्वकर्मा टीम ने 12 रनों से जीती



सोहागपुर । रेल्वे स्टेशन ग्राउंड पर स्वर्गीय मनोज खंडेलवाल स्मृति विधायक ट्राफी 3 नाइट प्रीमियर लीग टैनिस् क्रिकेट प्रतियोगिता के आठवें दिन चंद्रा इंटरप्राइजेज एवं विश्वकर्मा फर्नीचर एंड सी एन सी के बीच नाइट टैनिस् बाल प्रतियोगिता हुई। इस अवसर स्वर्गीय मनोज खंडेलवाल के पुत्र यश खंडेलवाल एवं आयोजक पार्श्व आशीष विश्वकर्मा मालवीय सहित भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता मंचासीन थे। नाइट टैनिस् बाल क्रिकेट प्रतियोगिता के आठवें दिन पहले बल्लेबाजी करते हुए विश्वकर्मा फर्नीचर ने निर्धारित ओवरों में 81 रन बनाए। इसके जवाब में चंद्रा इंटरप्राइजेज केवल 69 रन बनाकर टीम आउट हो गए। विश्वकर्मा फर्नीचर एंड सी एन सी टीम ने चंद्रा इंटरप्राइजेज को 12 रन से जीत दर्ज की। इस रोमांचक मुकाबले में विशाल मालवीय को मेन ऑफ द मैच के सम्मान से अतिथियों ने सम्मानित किया। स्वर्गीय मनोज खंडेलवाल स्मृति विधायक ट्राफी 3 नाइट टैनिस् बाल क्रिकेट प्रतियोगिता के आठवें दिन का आखों देखा हाल अंकित श्रोती एवं पवन रघुवंशी ने सुनाकर दर्शकों को आनंदित किया। इस रोमांचक मैच की स्कोरिंग परिणय मालवीय एवं नीरज कापड़े ने की। स्वर्गीय मनोज खंडेलवाल स्मृति विधायक ट्राफी 3 नाइट वलब प्रीमियर की अंपायरिंग अभिषेक टाकूर, हिमांशु शर्मा एवं हिमांशु जायसवाल ने की। आयोजक पार्श्व आशीष विश्वकर्मा मालवीय ने बताया कि स्वर्गीय मनोज खंडेलवाल स्मृति विधायक ट्राफी 3 नाइट वलब प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रथम विजेता को 81 हजार रुपए एवं ट्राफी से क्षेत्रीय विधायक विजयपालसिंह पुरुस्कार प्रदान करेंगे। उपविजेता टीम को 41 हजार एवं सील्ड से सम्मानित किया जाएगा। समापन समारोह में विशेष पुरुस्कार-मेन ऑफ द सीरिज, मेन ऑफ द मैच, वेस्ट बल्लेबाज, वेस्ट वॉलर, वेस्ट फ़िल्डर, वेस्ट विकेट कीपर, वेस्ट दर्शक, वेस्ट कैच, वेस्ट कॉमिन्टेटर, वेस्ट ऐम्पायर आदि के पुरुस्कार खिलाड़ियों को अतिथियों द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

## जनगणना 2027: प्रणक श्री चौधरी ने सर्वप्रथम कार्य पूर्ण किया एसडीएम ने प्रदान किया प्रमाण पत्र



सोहागपुर । जनगणना 2027 के प्रथम चरण अंतर्गत चार्ज सोहागपुर ग्रामीण में कार्यरत एचएलबी क्रमांक 0089 के प्रणक काशीराम चौधरी ने अपने निर्धारित गणना क्षेत्र का कार्य सर्वप्रथम पूर्ण कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की गई है। इस अवसर पर अनुविभागीय जनगणना अधिकारी एवं एसडीएम प्रियंका भल्लावी ने काशीराम चौधरी को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एसडीएम कार्यालय में प्रमाण पत्र प्रदान करके सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि श्री चौधरी ने अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा, लगन एवं जिम्मेदारी के साथ करते हुए समय-सौम्य के भीतर सभी जनगणना कार्यसफलतापूर्वक संपादित कर दिए हैं। अनुविभागीय जनगणना अधिकारी प्रियंका भल्लावी ने बताया कि इस प्रकार की उपलब्धियां अन्य प्रणकों के लिए प्रेरणास्रोत हैं तथा जनगणना कार्य के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करने में सहायक सिद्ध होती हैं। आपने जनगणना कार्य से जुड़े सभी प्रणकों एवं पर्यवेक्षकों से अपेक्षा की गई है कि वे भी इसी प्रकार समर्पण एवं जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें।

## सड़क सुरक्षा को लेकर एसडीएम एवं एसडीओ पुलिस ने स्वयं लगवाई ट्रेक्टर ट्राली पर रेडियम की पहियां



सोहागपुर । सोहागपुर विधानसभा के माखनगर ब्लाक के आंचल खेड़ा क्षेत्र में ट्रेक्टर-ट्राली एवं कार के बीच हुई भीषण सड़क दुर्घटना में 5 मृतक एवं इस हादसे में 7 से अधिक नागरिकों के घायल होने के बाद सोहागपुर ब्लाक के प्रशासनिक अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। ताकि ऐसी भीषण दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। इसी तारतम्य में अनुभाग सोहागपुर में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन के द्वारा एक सराहनीय पहल की गई। अनुविभागीय अधिकारी प्रियंका भल्लावी एवं एसडीओ पुलिस संजु चौहान के संयुक्त नेतृत्व में ट्रेक्टर-ट्रालियों पर रेडियम की पहियां लगाकर रात के समय होने वाले सड़क हादसों को रोकने का प्रयास किया गया। उल्लेखनीय है कि अक्सर देखा जाता है कि रात के अंधेरे में बिना किसी रिफ्लेक्टर या संकेत के चलने वाले ट्रेक्टर-ट्राली अन्य वाहनों के लिए खतरा बन जाते हैं। जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने स्वयं मौके पर पहुंचकर ट्रेक्टरों के पीछे रेडियम स्ट्रिप लगावाई, ताकि दूर से ही वाहन स्पष्ट दिखाई दे सकें। इसी अवसर आम नागरिकों एवं वाहन चालकों को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया और आवश्यक सावधानियों बताने की अपील की गई। प्रशासन ने बताया कि इस तरह के अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे, जिससे दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। उल्लेखनीय है कि यह इस क्षेत्र में प्रथम अवसर पर जब प्रशासनिक एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने स्वयं किसी वाहनों में रेडियम पहियां लगाने का कार्य किया है। ज्ञातव्य है कि सोहागपुर विधानसभा के माखन नगर का ट्रेक्टर ट्राली एवं कार भिड़ंत हादसा दिल-दहलाने वाली घटना थी।

## अनुकरणीय संवेदनशीलता

# लीज प्रकरण मामले में एसडीएम ने न्यायालयीन सीट से उठकर पहुंची दिव्यांग पंकज सोनी तक

सोहागपुर । कभी-कभी मानवीय संवेदना अनुकरणीय संवेदनशीलता का उदाहरण बन जाता है। ऐसा ही उदाहरण सोहागपुर विधानसभा के मुख्यालय में अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में एसडीएम प्रियंका भल्लावी की अदालत में देखने को मिला। जिसमें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय में मंगलवार को लीज नवीनीकरण से संबंधित प्रकरण दिव्यांग पंकज सोनी ने दिया था। जिसकी सुनवाई निर्धारित थी। उल्लेखनीय है कि दिव्यांग पंकज सोनी जिनके पैर बचपन में सोहागपुर रेल्वे स्टेशन पर एक ट्रेन से हादसे में उलटते समय रेल में आ जाने से दोनों पैरों को उनका जीवन बचाने के लिए आग्रेशन करना पड़ा था। इस सुनवाई के अक्सर पर एसडीएम प्रियंका भल्लावी ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए अपनी सीट (डेस्क) से नीचे आकर आवेदक की बात सुनी। इस संवेदनशीलता के कारण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय में उपस्थित प्रत्यक्षदर्शियों ने एसडीएम प्रियंका भल्लावी के जनता-जनार्दन के प्रति सहानुभूति एवं समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत किया है। जिसकी सभी ने सराहना की। ज्ञातव्य है कि पंकज सोनी के दोनों पैर न होने के उपरांत भी उन्होंने बचपन से ही शिक्षा के प्रति समर्पण



एवं कुछ कर सकने इच्छा शक्ति से निरंतर आगे बढ़ते रहे। पंकज सोनी की गिनती कामयाब नागरिकों में होती है। वहीं वर्तमान में पिपरिया नर्मदापुरम राज्य मार्ग पर उनकी आनलाइन दुकान है। जिसमें सभी आनलाइन कार्य करते हैं। यदि किसी में भी जीवन जीने के ललक है

तो भले दिव्यांग हो तो यह दिव्यांगता भी सीखने भी बाधक नहीं बनती है। प्रशासन के द्वारा उक्त घटना सभी नागरिकों, विशेषकर दिव्यांगजनों की सुविधाओं तरफ सम्मान की तरफ सहानुभूति एवं मानवीय कर्तव्य करने की तरफ इंगित करती है।

# 17 केन्द्रों पर कुल 8177 परीक्षार्थी दोबारा देंगे बोर्ड परीक्षा

## आज से शुरू होगी 10वीं-12वीं की द्वितीय परीक्षा

एस. द्विवेदी, बैतूल। माध्यमिक शिक्षा मंडल मप्र की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं के अनुत्तीर्ण व अक्सर चाहने वाले विद्यार्थियों के लिए सप्लीमेंट्री के स्थान पर द्वितीय परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। यह परीक्षा आज 7 मई से शुरू होकर 25 मई तक चलेगी। इसके लिए जिले के विकासखंडों में 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 8177 परीक्षार्थी दोबारा बोर्ड परीक्षा देंगे। परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मंगलवार को जिला मुख्यालय स्थित शासकीय उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में सभी परीक्षा केंद्रों के लिए गोपनीय सामग्री का वितरण किया गया। गोपनीय सामग्री को केंद्र प्रभारियों को पुलिस सुरक्षा के साथ वाहनों से संबंधित थानों तक पहुंचाया गया, जहां से आज यह गोपनीय सामग्री परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले थाने से केंद्र पर



पहुंचाया जाएगा। 10वीं-12वीं दोनों कक्षाओं के लिए सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक समय रहेगा। परीक्षा के लिए केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है।

उद्देश्य: योग्यता सुधारने और निष्पक्ष मार्कशीट देना - द्वितीय परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को शैक्षणिक तनाव से मुक्त करते हुए उन्हें अपनी योग्यता सुधारने का एक और अवसर देना है। इस व्यवस्था में सप्लीमेंट्री जैसा नकारात्मक टैग नहीं होगा और विद्यार्थियों को अंकों

में सुधार का लाभ मिलेगा। मुख्य और द्वितीय परीक्षा में प्राप्त श्रेष्ठ अंकों के आधार पर अंतिम परिणाम तैयार किया जाएगा। जिससे छात्रों को सम्मानजनक और निष्पक्ष मार्कशीट मिल सकेगी।

हिन्दी के पेपर से शुरू होगी परीक्षा- पहले दिन आज गुरुवार को कक्षा 10वीं का हिन्दी विषय का पेपर होगा। कक्षा 12वीं में बायोटेक्नोलॉजी का प्रश्नपत्र निर्धारित है, हालांकि जिले में इस विषय की पढ़ाई नहीं होने के कारण यह परीक्षा आयोजित नहीं होगी। दूसरे दिन शुक्रवार को कक्षा 12वीं का हिन्दी विषय का पेपर लिया जाएगा। कक्षा 10वीं की

परीक्षाएं 7 मई से 19 मई तक व कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 8 मई से 25 मई तक चलेगी। बताया जा रहा है कि परीक्षा समाप्त होने के लगभग 10 दिन के भीतर परिणाम घोषित किए जाएंगे।

10वीं के 3908 और 12वीं के 4269 विद्यार्थी होंगे शामिल- माध्यमिक शिक्षा मंडल मप्र द्वारा आयोजित द्वितीय परीक्षा में कक्षा 10वीं और 12वीं के कुल 8177 परीक्षार्थी दोबारा बोर्ड परीक्षा देंगे। जिसमें कक्षा 10वीं के 3908 विद्यार्थी और कक्षा 12वीं के 4269 विद्यार्थी शामिल हैं। परीक्षा के लिए जिले के विकासखंडों में कुल 17 परीक्षा केंद्र बनाये गये हैं। एक केंद्र पर कम से कम 225 विद्यार्थियों से लेकर अधिकतम 600 विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा नकलचियों को पकड़ने के लिए उडनदस्ते भी बनाये गये हैं। जो केंद्रों का निरीक्षण कर नकलचियों पर नजर रखेंगे।

जिले में परीक्षा के लिए बनाये 17 केंद्र- जिले में 10वीं-12वीं की द्वितीय परीक्षा के लिए कुल 17 केंद्र का पेपर लिया जाएगा। कक्षा 10वीं की

कन्या उ. मा. वि. बैतूल, शा. कन्या उ. मा. वि. बैतूलगंज, शा. कन्या उ. मा. वि., बैतूल बाजार, शा. सांदीपनी कृषि उ. मा. वि. बैतूल बाजार, बैतूल, शा. सांदीपनी उ. मा. वि. मुलताई, शा. सांदीपनी बालक उ. मा. वि., भैसदेही, शा. सांदीपनी अ. जा. क. उ. मा. वि., शाहपुर, शा. बालक केंद्र पर कम से कम 225 विद्यार्थियों से लेकर अधिकतम 600 विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा नकलचियों को पकड़ने के लिए उडनदस्ते भी बनाये गये हैं। जो केंद्रों का निरीक्षण कर नकलचियों पर नजर रखेंगे।

इनका कहना है - माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित द्वितीय परीक्षा की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। गोपनीय सामग्री का वितरण किया जा चुका है। गुरुवार 7 मई से सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित होंगी।

- सत्येन्द्र उदयपुरे, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, बैतूल

## रेत, गिट्टी और बोल्टर के अवैध परिवहन में सलिस 3 वाहनों को किया जप्त

बैतूल। कलेक्टर डॉ. सौरभ सोनवणे के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनिज परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत बुधवार को खनिज विभाग द्वारा खनिज अमले के साथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। खनिज अमले द्वारा गौण खनिजों के अवैध परिवहन में सलिस वाहनों पर कार्यवाही करते हुए उन वाहनों को जप्त कर समीपस्थ पुलिस थानों की अभिरक्षा में खड़ा करवाया गया है। खनिज प्रशासन उप संचालक एवं खनिज निरीक्षक बैतूल द्वारा खनिज अमले के साथ मुलताई क्षेत्रांतर्गत ग्राम परमंडल के पास से खनिज गिट्टी के अवैध परिवहन में सलिस 01 वाहन डम्पर क्रमांक एमपी 48 एच 0625 को जप्त कर पुलिस थाना साईंखेड़ा की अभिरक्षा में खड़ा करवाया गया है। वहीं, बैतूल क्षेत्रांतर्गत बैतूल बाजार के पास से खनिज बोल्टर के अवैध परिवहन में सलिस 01 वाहन डम्पर क्रमांक एमएच 12 डब्ल्यूजे 9371 को जप्त कर पुलिस थाना बैतूल बाजार की अभिरक्षा में खड़ा करवाया गया है।



## पशुपालन में बैतूल का भवानीतेड़ा गांव बनेगा मॉडल

### क्षीर धारा ग्राम योजना पर संगोष्ठी हुई

बैतूल। पशुपालन के क्षेत्र में उन्नतशील ग्रामों को उदाहरणीय एवं आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से चलाई जा रही क्षीर धारा योजना के सफल क्रियाव्ययन हेतु बैतूल के ग्राम भवानीतेड़ा को पूर्ण विकसित करने पशुपालन एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ बुधवार को संगोष्ठी का आयोजन किया। इसमें पशु प्रजनन कार्यक्रम अधिकारी डॉ. चंचल मेश्राम ने क्षीर धारा ग्राम योजना की विस्तार से जानकारी देते हुए नस्ल सुधार, पशु स्वास्थ्य एवं पशु पोषण के विषय में बताया। नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान एवं सेक्स साईटिंग सीमेन का महत्व, पशु स्वास्थ्य एवं पशु पोषण में हरे चारे की उपयोगिता, समयबद्ध टीकाकरण कार्यक्रम, कृमिनाशन का महत्व बताया। साथ ही पशुओं को संतुलित आहार के लिए गोरस एप की जानकारी दी।

सहायक संचालक महुवा कल्याण एवं मत्स्य पालन कमलेश खरे ने तालाब निर्माण कर मछली पालन करने एवं उससे होने वाले लाभ



की जानकारी दी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहायक विकासखंड प्रबंधक चन्द्रबली ठाकरे ने आजीविका मिशन के अंतर्गत खेतों में तालाब बनाने के लिए योजनाओं की जानकारी दी। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के बी.टी.एम. विजयेंद्र वाईकर ने जैविक

खेती एवं प्राकृतिक खेती के विषय में जानकारी देते हुए इससे होने वाले लाभ एवं पशुओं के महत्व पर जानकारी दी। कृषि विस्तार अधिकारी संतोष बोरबन ने बायो गैस संयंत्र, बर्मी कम्पोस्ट एवं चारा फसलों के विषय में विस्तार से बताया। संगोष्ठी के दौरान डॉ. राज कमल मेश्राम एवं सुश्री नम्रता भारती ने ग्रामीणों द्वारा लाए गए पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान, गर्भ परिक्षण एवं बाइपिन निवारण उपचार किया। संगोष्ठी में ग्रामीण जन एवं स्वसहायता समूह की महिलाओं ने चर्चा में भाग लेते हुए उन्नत पशुपालन, हरा चारा उत्पादन एवं प्राकृतिक, जैविक खेती को ग्राम में बढ़ावा देने एवं कृषि

तथा पशुपालन को लाभ का व्यवसाय बनाने में ग्रामीणों की भागीदारी का आग्रह किया। इस मौके पर उपस्थित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने ग्रामीणों से चर्चा कर सफल क्रियाव्ययन के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने का निर्णय लिया।

## धार के नाथ की शरण में नवागत कलेक्टर राजीव रंजन मीना, पदभार ग्रहण करते ही दिखे एक्शन में धार जिला देख रहा आशा भरी निगाहों से - तथा नवागत कलेक्टर बनेंगे बदलाव की उम्मीद

### धार से राजेश शर्मा

धार के नाथ की शरण में नवागत कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने धारेश्वर मंदिर में पूजन- अर्चन कर पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते ही दिखे एक्शन में। ऐसे में धार जिला नवागत कलेक्टर को आशा भरी निगाहों से देख रहा है कि वे बदलाव की उम्मीद बनेंगे। नवागत कलेक्टर के सख्त तेवरों से साफ है कि आने वाले दिनों में जिले की प्रशासनिक मशीनरी को रफ्तार बढ़ाने वाली है। अधिकारियों को अब 'परफॉर्मेंस' दिखाना होगा। महज दो दिनों में धार जिले का प्रशासनिक इकोसिस्टम बदल गया है। कल 5 मई मंगलवार को पुलिस कमान (एसपी) के रूप में सचिन शर्मा की ताजपोशी हुई और आज राजीव रंजन मीना ने बतौर डीएम जिले के मुखिया के रूप में बागडोर संभाल ली। प्रदेश के मानचित्र पर धार प्रदेश के बड़े जिले और विविधताओं के लिए जाना जाता है ऐसे में नवागत कलेक्टर और पुलिस कमान

की कार्यशैली आशा की किरण के रूप में देखी जा रही है। बीते कुछ समय में प्रशासनिक हलचल और घंटित हादसों - दुर्घटनाओं ने इस संभावनाशील जिले के माथे पर कई बदनुमा दाग लगाए हैं। ऐसे में यह जिला और यहां के बाशिंदे बदलाव की उम्मीद लगाए हुए हैं। स्वाभाविक तौर पर बहुत आशाएं हैं धार जिले को अपने प्रशासनिक मुखिया नवागत कलेक्टर राजीव रंजन मीना से। नवागत कलेक्टर मीना कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे जहां मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभिषेक चौधरी, अपर कलेक्टर संजीव केशव पाण्डेय सहित अधिकारियों ने स्वागत किया।



कलेक्टर ने अपनी 'वकिंग स्टाइल' के संकेत दिए, टीएल बैठक के टारगेट समय पर पूरे करें,

बहानेबाजी नहीं चलेगी - जिले के नवागत कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने कार्यभार संभालते ही अपनी 'वकिंग स्टाइल' के संकेत दिए हैं। बुधवार को



कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित पहली परिचयात्मक बैठक में उन्होंने जिले के तमाम आला अफसरों को स्पष्ट कर दिया कि विकास कार्यों में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

रैंकिंग सुधारों वरना जवाबदेही तय होगी - कलेक्टर ने शासन की योजनाओं को लेकर अधिकारियों की क्लास ली। उन्होंने रैंकिंग पर फोकस रखने पर जोर देते हुए कहा शासन स्तर पर सचिव हर विभाग की समीक्षा करते हैं। जिले का प्रदर्शन टॉप पर होना चाहिए, अपनी स्थिति अपडेट रखें।

'रिपोट कार्ड' तैयार रखें अफसर. - कलेक्टर मीना ने सभी जिला प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने विभाग की प्रमुख योजनाओं, चल रहे प्रोजेक्ट्स और वीसी (VC) में मिलने वाले निर्देशों का पूरा डेटा तत्काल उपलब्ध कराएं। कलेक्टर डेड मॉनिटरिंग करेंगे कि किस विभाग ने कितना काम किया है। धार का विकास: इंफ्रा और



पर्यटन पर रहेगा जोर - जिले की भौगोलिक और औद्योगिक स्थिति को देखते हुए कलेक्टर ने भविष्य का विजन भी साझा किया। उन्होंने कहा कि जिले में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिकरण के प्रोजेक्ट्स प्रशासन की रडार पर रहेंगे। धार और मांडू जैसे पर्यटन क्षेत्रों के विकास और आगामी आयोजनों के लिए प्रशासन को अभी से 'अलर्ट मोड' पर रहने के निर्देश दिए हैं।

## सूचना का अधिकार

अरुण कुमार डनायक

लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।



केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा रूस से भारत के कच्चे तेल आयात संबंधी विस्तृत जानकारी को सार्वजनिक करने से इनकार को 27 अप्रैल 2026 के हलिया फैसले में बरकरार रखा गया, जो एक बार फिर यह प्रश्न उठाता है कि पारदर्शिता और राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन कहाँ स्थापित किया जाए। आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(d)–जो वाणिज्यिक गोपनीयता, व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा से जुड़ी ऐसी सूचनाओं को सार्वजनिक करने से छूट देती है, जिसे किसी तृतीय पक्ष की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति प्रभावित हो सकती है–और धारा 8(1)(e)–जो विश्वासगत संबंध में प्राप्त सूचनाओं के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करती है–का हवाला देते हुए कहा कि कंपनी-वार आयात डेटा में मूल्य निर्धारण, अनुबंध, छूट और व्यापारिक रणनीतियों जैसी संवेदनशील जानकारीयें शामिल होती हैं, जिन्हें सरकारी विश्वासता आधार पर प्राप्त करती है; अतः इनके प्रकटीकरण को छूट के दायरे में रखा जाना उचित है। इस प्रकार आयोग ने पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (पीपीएसी) के उस निर्णय को सही ठहराया, जिसमें जून 2022 से जून 2025 के बीच रूस से आयातित कच्चे तेल का कंपनीवार और विस्तृत देशवार विवरण देने से मना किया गया था। पीपीएसी, पेट्रोलियम

और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का एक प्रमुख तकनीकी विश्लेषणात्मक विंग है, जो डेटा संग्रह, विश्लेषण और नीति समर्थन के माध्यम से देश को ऊर्जा सुरक्षा और पेट्रोलियम अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। यह फैसला सूचना के अधिकार अधिनियम की मूल भावना पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। आवेदक ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों, रिलायंस और नायर एनर्जी के लिए अलग-अलग आंकड़े मांगे थे। हालाँकि आयोग ने अपील खारिज कर दी, लेकिन साथ ही पीपीएसी को आरटीआई अधिनियम की धारा 4 और 25(5) के तहत स्वप्रेरित पारदर्शिता बढ़ाने के निर्देश भी दिए। यह रूख आयोग के उस प्रयास को दर्शाता है, जिसमें वह गोपनीयता और सार्वजनिक सूचना के बीच संतुलन साधना चाहता है। फिर भी, विस्तृत आयात डेटा को छूट देते हुए पारदर्शिता बढ़ाने के निर्देश देना कुछ हद तक विरोधाभासी प्रतीत होता है। यह निर्णय ऐसे समय आया है जब रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रियायती रूसी तेल आयात बढ़ाया और 2024-25 में रूस उसका प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन गया; वैश्विक प्रतिबंधों, मध्यपूर्व तनाव और अमेरिका के दबाव रियायत केबीच भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को संतुलित करता रहा है। सरकार का तर्क है कि कई देशों में संवेदनशील व्यापारिक डेटा को गोपनीय रखना सामान्य प्रथा है। ऊर्जा आयात अब केवल आर्थिक नहीं, बल्कि रणनीतिक भूराजनीतिक विषय है; इसलिए यह

जानकारी सार्वजनिक करने से कंपनियों को सौदेबाजी क्षमता कमजोर हो सकती है और अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण राष्ट्रीय हित प्रभावित हो सकते हैं। गोपनीयता के ऐसे फैसलों से यह प्रश्न भी उठता है कि कहीं सरकार अंतरराष्ट्रीय दबाव-विशेषकर अमेरिका की संभावित नाराजगी-से बचने के लिए सूचनाओं के प्रकटीकरण में अतिरिक्त सावधानी तो नहीं बरत रही। यह प्रवृत्ति नई नहीं है; रक्षा, ऊर्जा और कूटनीति जैसे क्षेत्रों में डेटा साझा करने में सावधानी बरतना लंबे समय से राज्य की नीति रही है, क्योंकि इन क्षेत्रों में सूचना को शक्ति माना जाता है।

सरकार के तर्कों के बावजूद पारदर्शिता की कुछ गुंजाइश फिर भी है। तेल बाजार अत्यंत अपारदर्शी है। प्रतिबंधित देश पहचान छिपाने हेतु अक्सर गुप्त जहाजों, ध्वज-परिवर्तन जैसे तरीकों से व्यापार करते हैं। ऐसे में यदि कंपनी या देश-वार डेटा सार्वजनिक न हो, तो तेल के वास्तविक स्रोत, कीमत, संभावित अनिश्चितताओं तथा अंतरराष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन का आकलन कठिन हो जाता है। सस्ते कच्चे तेल का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँच रहा है यानहीं, यह स्पष्ट नहीं हो पाता है। जिससे बाजार पारदर्शिता और देश की विश्वसनीयता दोनों प्रभावित होती हैं।

सुरीम कोर्ट के कई फैसलों में स्पष्ट किया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत छूट तभी लागू हो सकती है, जब सूचना के खुलासे से वास्तविक

और प्रमाणित नुकसान हो तथा सार्वजनिक हित उससे अधिक न हो। सुरीम कोर्ट के स्थापित सिद्धांत स्पष्ट करते हैं कि सूचना का खुलासा नियम है और गोपनीयता अपवाद। सीआईसी ने अपने निर्णय में ऐसा प्रतीत होता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(2) अलग से परीक्षण नहीं किया है, जो स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करती है कि धारा 8(1) के तहत दी गई किसी भी छूट के बावजूद, यदि सूचना के प्रकटीकरण से होने वाला जनहित उसे रोकने से होने वाले संभावित नुकसान से अधिक हो, तो संबंधित प्राधिकरण को वह सूचना उपलब्ध करानी चाहिए। तेल आयात का डेटा स्पष्ट रूप से सार्वजनिक हितसे जुड़ा है, क्योंकि यह ऊर्जा सुरक्षा, मूल्य पारदर्शिता, सस्ते कच्चे तेल का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचाने और नीति की प्रभावशीलता से सीधे संबंधित है। कंपनीवार जानकारी न होने से यह आकलन कठिन हो जाता है कि आयातका लाभ पूरी तरह उपभोक्ताओं तक पहुँच रहा है या कुछ सौदे महीने पड़ रहे हैं, जिससे नीति मूल्यांकन सीमित होता है और जवाबदेही कमजोर पड़ती है। यह 'नियंत्रित पारदर्शिता' का मॉडल है, जिसमें आँकड़ों की झलक तो मिलती है, लेकिन असली तस्वीर सूक्ष्म गोपनीयता के पर्दे के पीछे ही रहती सीआईसी का यह रुख संकेत देता है कि हाल के वर्षों में वह पारदर्शिता की तुलना में संवेदनशील सूचनाओं पर अधिक सतर्क और प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण अपना रहा है। यह राष्ट्रीय

सुरक्षा और रणनीतिक हितों की ओट में सूचना को सीमित रखने की प्रवृत्ति है, जिससे रक्षा सौदे सहित कई संवेदनशील क्षेत्रों में जानकारी रोकी गई है, और इससे पारदर्शिता घटने के साथ-साथ संभावित अनिश्चितताओं या भ्रष्टाचार की प्रभावी जांच और पहचान की क्षमता भी सीमित होती है, जिससे सूचना के अधिकार की मूल भावना-खुलासा नियम और छूट अपवाद-कमजोर पड़ने का खतरा बढ़ता है।

आधुनिक ऊर्जा और भू-राजनीतिक परिदृश्य में पूर्ण अपारदर्शिता न तो संभव है और न ही वांछनीय, लेकिन जब गोपनीयता का दायरा लगातार विस्तृत होता जाए और पारदर्शिता अपवाद बन जाए, तो लोकतांत्रिक जवाबदेही पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। इसलिए ऊर्जा क्षेत्र में पारदर्शिता केवल प्रशासनिक आवश्यकता नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक जवाबदेही का मूल आधार है, और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि गोपनीयता सार्वजनिक हित तथा नागरिकों के सूचना अधिकार को पीछे न धकेले। भविष्य में ऐसे मामलों में बेहतर संतुलन स्थापित करना आवश्यक है, ताकि राष्ट्रीय हित और पारदर्शिता दोनों सुसुचित रह सकें। इसके लिए आवश्यक है कि पीपीएसी जैसी संस्थाएँ वार्षिक स्तर पर विस्तृत ग्रेनर डेटा और त्रैमासिक स्तर पर देश-वार आयात आँकड़े नियमित रूप से प्रकाशित करें, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़े, विशेषज्ञ विश्लेषण संभव हो और सार्वजनिक हित प्रभावी रूप से सुरक्षित रह सके।

## जल गंगा अभियान के तहत गिलाडिया घाट पर चलाया गया स्वच्छता अभियान श्रद्धालुओं से स्वच्छता बनाए रखने के लिए की गई अपील

**नर्मदापुरम (निप्र)।** जल गंगा अभियान के अंतर्गत शिवपुर सेक्टर क्रमांक 02 में नवांकुर संस्था दिशा जन कल्याण सेवा समिति, कोलगांव द्वारा ग्राम पंचायत भिलाडिया घाट पर प्रस्फुटन समिति के सदस्यों के साथ मिलकर माँ नर्मदा के घाट की साफ-सफाई की गई। इस दौरान घाट परिसर में फैली गंदगी को हटाकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। संस्था अध्यक्ष श्री योगेंद्र सिंह राजपूत ने सभी श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि माँ नर्मदा के घाटों पर गंदगी न करे और उन्हें स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने में सहयोग दें। उन्होंने कहा कि माँ नर्मदा को सदानेवा बनाए रखने के लिए नर्मदा जल में पूजा सामग्री विसर्जित नहीं करना चाहिए। इस अवसर पर परामर्शदाता सुशी नेहा यादव सहित प्रस्फुटन समिति के सदस्य-सबर सिंह, रामशंकर, सियायाम, सुरेश कुशवाहा एवं कान्हा कुशवाहा उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प लिया और जनसामान्य को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया।

## देवनागर में 12 मई को आयोजित होगा

### जिला स्तरीय युवा संगम मेला

**रायसेन (निप्र)।** जिले के बेरोजगार युवाओं को रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कलेक्टर श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा के निर्देशानुसार 12 मई 2026 को गैरतमंग विकासखण्ड के देवनागर स्थित पीएमश्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय युवा संगम मेले का आयोजन किया जा रहा है। जिला रोजगार कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा कौशल विकास विभाग के संयुक्त तत्वधान में आयोजित यह युवा संगम मेला 12 मई को प्रातः 11 बजे से अपराह्न 03 बजे तक आयोजित होगा। इस युवा संगम मेले के माध्यम से युवाओं को विभिन्न कम्पनियों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने के साथ ही शासन की स्वरोजगारमूलक योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। इस जिला स्तरीय युवा संगम मेले में नवभारत फटीलाइजर भोपाल, भास्कर मण्डीदीप, आईपीएस भोपाल, इंसुलेटर एण्ड इलेक्ट्रिकल्स मण्डीदीप, शयक्वी ग्रुप मण्डीदीप, सागर मेनिफेक्चर तामोट, होम हेल्प सेंटर रायसेन, हकाई सिकरोटी मण्डीदीप, आर सेटी रायसेन, वोल्को आयरशर वगैरों, पुखराज प्रा.लि. भोपाल समर्थन ट्रस्ट भोपाल द्वारा विभिन्न पदों पर युवाओं की भर्ती की जाएगी। इसके लिए अनिवार्य योग्यता पदानुसार कक्षा 8वीं, 10वीं, 12वीं, स्नातक, आईटीआई, डिप्लोमा इंजीनियरिंग एवं डिग्री इंजीनियरिंग है। आयु सीमा 18 वर्ष से 35 वर्ष निर्धारित है। इस अवसर पर ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं का स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं उन्हें विभिन्न स्वरोजगारमूलक विभागों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा और शासन की ओर से दी जाने वाली सहायता एवं योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी।

## जिले में कहीं भी शासकीय भूमि या नदी किनारे ईट-भट्टों का संचालन ना होने पाए : कलेक्टर

**विदिशा (निप्र)।** कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने आज लंबित आवेदनों की गहन समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले में कहीं भी शासकीय जमीनों या नदी किनारे अवैध ईट भट्टों का संचालन नहीं होने पाए। यदि शासकीय जमीनों या नदी किनारों पर ईट भट्टों का संचालन पाया जाता है तो इस पर स्थानीय एसडीएम और तहसीलदार सख्त कार्यवाही करेंगे। इसके लिए उन्होंने बैठक में वचुंअल जुड़े जिले के सभी अनुविभागी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बैठक में श्रम विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने श्रमोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में लापरवाही बरतने पर श्रम अधिकारी और डीपीसी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पीएम श्रम योगी मानधन योजना के कार्यों, शासकीय सेवकों के पेंशन के लंबित प्रकरणों, न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण कार्यों की भी

समीक्षा की गई है। कलेक्टर श्री गुप्ता ने सीएम मॉनिट तहत लंबित प्रकरणों की समीक्षा भी की है उन्होंने ऑनलाइन वीसी के माध्यम से जुड़े स्तरीय अधिकारियों से संवाद कर इन प्रकरणों के प्रतिवेदन भेजे हैं या नहीं भेजे के संबंध में चर्चा की और प्रकरणों का हल करने के लिए शीघ्र अति शीघ्र जिला कार्यालय को प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि कोई भी अधिकारी बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। विचार कर शासकीय अवकाश में भी वह बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। बैठक के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं के संबंध में भी कलेक्टर ने दिशा-निर्देश दिए हैं इस दौरान उन्होंने एनआरसी वार्ड में भर्ती बच्चों की जानकारी भी प्राप्त कर क्रियान्वित कार्यों का जायजा लिया।

## मकान सूचीकरण में अच्छा कार्य करने वाले प्रगणकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर दिया सम्मानित

### टीएल बैठक में कलेक्टर

### श्री विश्वकर्मा ने की

### जनगणना, सीएम

### हेल्पलाईन और

### शासकीय कार्यों की

### समीक्षा

**रायसेन (निप्र)।** कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित टीएल बैठक में कलेक्टर श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा द्वारा जनगणना-2027, गैहू उपाजिन केन्द्रों पर तैल काटे बढ़ाने, पंजीयन, खरीदी, सीएम हेल्पलाईन, विभागीय गतिविधियों, समय सीमा वाले पत्रों, योजनाओं तथा अभियानों की साप्ताहिक प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के



प्रारंभ कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने जनगणना-2027 के कार्यों की विकासखण्डवार एसडीएम से अपने क्षेत्र में हुए कार्यों की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने गैहू उपाजिन केन्द्रों पर तैल काटे बढ़ाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने 01 मई से प्रारंभ हुए जनगणना-2027 मकान सूचीकरण के कार्यों के लिए सभी एसडीएम, को अपनी टीम के साथ

अपने-अपने क्षेत्रों में किए कार्यों और रणनीति के बारे में विस्तृत समीक्षा की। साथ ही उन्होंने जनगणना-2027 मकान सूचीकरण के कार्यों को जिम्मेदारी, मेहनत और लगन के साथ करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों तथा प्रगणकों की सराहना भी की। बैठक में प्रगणकों द्वारा अपना-अपना कार्यों का अनुभव जैसे कि एचएलवी, नगरीय नक्शा, लोकेशन आदि किए गए कार्यों को

भी साझा किया। बैठक में जनगणना-2027 में 01 मई से प्रारंभ मकान सूचीकरण में अच्छा कार्य करने वाले प्रगणकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित भी किया गया।

बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने सीएम हेल्पलाईन शिकायतों के निराकरण की विभागवार विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सीएम हेल्पलाईन शिकायतों का संशुद्धिपूर्ण निराकरण कराने के निर्देश दिए। साथ ही 50 दिवस से अधिक समयवर्ध की शिकायतों का भी प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में लोक निर्माण विभाग, खनिज विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, उद्यानिकी सहित अन्य विभागों की समीक्षा करते हुए दिशा-निर्देश दिए गए।

## पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए नागरिकों एवं संस्थाओं को किया जाए जागरूक

## 12वीं पास कोई भी विद्यार्थी उच्च शिक्षा से न छूटे : कलेक्टर

**जनगणना एवं जल गंगा संवर्धन अभियान में अपेक्षित गति नहीं होने पर कलेक्टर ने जताई नाराजगी, तेजी लाने के लिए निर्देश**

### कलेक्टर की अध्यक्षता में टीएल बैठक आयोजित

**सोहोर (निप्र)।** कलेक्टर श्री बालागुरु के. की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में टीएल बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने सभी विभागों के समय-सीमा वाले प्रकरणों और सीएम हेल्पलाईन में लंबित प्रकरणों की समीक्षा की और समय सीमा के भीतर सभी प्रकरणों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरु के. ने विभिन्न शासकीय योजनाओं और अभियानों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में जल गंगा संवर्धन अभियान, जनगणना, वन मित्र पोर्टल पर वनाधिकार दावों के पंजीयन, कॉलेजों में प्रवेश तथा समग्र इ-केवाईसी जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इन अभियानों में लापरवाही बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जाएगी।



सभी संबंधित अधिकारी अपने-अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करें। कलेक्टर ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कार्यों में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों को समय-सीमा में लक्ष्य पूर्ण करने और जमीनी स्तर पर परिणाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिले में संचालित विभिन्न शासकीय कार्यों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने जनगणना कार्य में अपेक्षित गति नहीं होने पर नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनगणना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है, जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी

अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करें और निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर ने जल गंगा संवर्धन अभियान की प्रगति की भी समीक्षा की। इस दौरान अभियान की धीमी गति पर असंतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने निर्देशित किया कि अभियान के अंतर्गत अधिक से अधिक गतिविधियाँ आयोजित की जाएँ। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, इसलिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करते हुए जनभागीदारी बढ़ाएँ। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गाँव-गाँव में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ, जिससे आमजन को जल संरक्षण के प्रति प्रेरित किया जा सके।

## कृत्रिम पैरों से उमा के आत्मविश्वास और सपनों को मिली नई उड़ान

**सोहोर (निप्र)।** शासन द्वारा समाज के प्रत्येक वर्ग के समग्र कल्याण और उन्हें सम्मानजनक एवं आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से अनेक जनकल्याणकारी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। इन्हीं में से एक है 'एडिप योजना', जो दिव्यांगजनों के जीवन में नई रोशनी और आत्मविश्वास का संचार कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे जरूरतमंदों को समय पर आवश्यक सहायता मिल रही है।

सोहोर निवासी श्रीमती उमा चौरसिया के लिए यह योजना विशेष वरदान से कम नहीं रही। जब उन्हें जानकारी मिली कि सामाजिक न्याय विभाग द्वारा सोहोर में विशेष शिविर आयोजित कर दिव्यांगजनों को ऑन द स्पॉट कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए

जाएँ, तो वे निर्धारित समय पर शिविर में पहुँचीं। शिविर में उनका पंजीयन किया गया और विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण उपरांत उन्हें वहीं निःशुल्क कृत्रिम पैर प्रदान किए गए। साथ ही उन्हें उपयोग में सुविधा के लिए आरामदायक जूते भी निःशुल्क उपलब्ध कराए गए।



कृत्रिम पैर प्राप्त करने के बाद श्रीमती चौरसिया के चेहरे पर खुशी और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा कि अब वे पहले की अपेक्षा अधिक सहजता से अपने दैनिक कार्य कर सकेंगी और आत्मनिर्भर जीवन जी पाएँगी। उन्होंने प्रदेश सरकार एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना उनके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आई है। एडिप योजना के माध्यम से शासन ने केवल दिव्यांगजनों को सहारा दे रहा है, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ते हुए उनके जीवन को नई दिशा दे रहा है।

## पुस्तक समीक्षा

दीपक गिरकर

समीक्षक



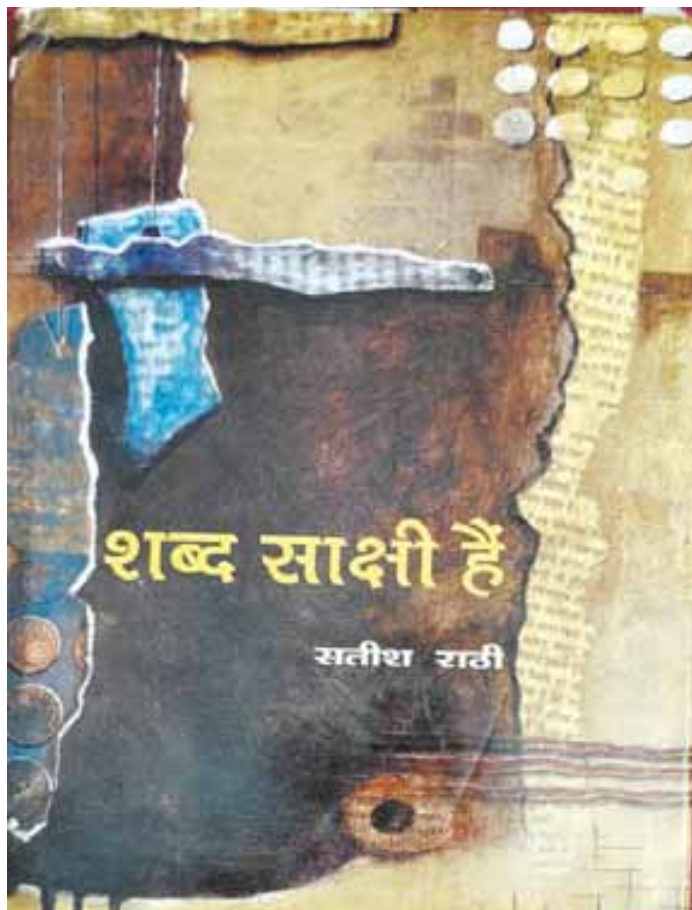
हिंदी साहित्य के आकाश में सतीश राठी की सुजनधर्मिता एक दीप नक्षत्र की भाँति आलोकित है। सतीश राठी की संवेदनशील, सजग और सशक्त लेखनी ने न केवल एक विशिष्ट पहचान अर्जित की है, अपितु समकालीन साहित्य को गहन अर्थवत्ता भी प्रदान की है। इनकी रचनाएँ समय की धड़कनों को सुनती हैं, समाज की विसंगतियों को पहचानती हैं और मानवीय मूल्यों की ऊष्मा को अत्यंत मार्मिकता के साथ अभिव्यक्त करती हैं। विशेषतः लघुकथा विधा को सतीश राठी ने जिस साधना, सूक्ष्म दृष्टि और शिल्प-संपन्नता के साथ साधा है, वह हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। इनकी लघुकथाएँ केवल कथ्य नहीं, बल्कि समय-साक्षी दस्तावेज बनकर पाठकों के अंतर्मन को स्पर्श करती हैं। इनकी रचनाएँ विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित होकर नई पीढ़ी को संवेदनशील दृष्टि दे रही हैं और विभिन्न भाषाओं में अनूदित होकर व्यापक पाठक-समाज तक पहुँच रही हैं। शिथिल साहित्यिक संस्था के माध्यम से सतीश राठी का मार्गदर्शन अनेक नवांकुर रचनाकारों के लिए प्रेरणास्रोत रहा है। इन्होंने युवा लेखकों को केवल प्रोत्साहन ही नहीं दिया, बल्कि उनकी सुजनात्मक चेतना को दिशा और संस्कार भी प्रदान किए। इंदौर से लघुकथा के क्षेत्र में उभरती सशक्त उपस्थिति सतीश राठी की साहित्य-सेवा का उज्ज्वल परिणाम है।

सतीश राठी का साहित्यिक स्थान आज भारतीय लघुकथा-जगत में अत्यंत प्रतिष्ठित और सम्मानित माना जाता है। यह प्रतिष्ठा उन्हें केवल रचनाओं की संख्या के कारण नहीं,

## संवेदनाओं और सामाजिक यथार्थ की सूक्ष्म, किंतु सशक्त अभिव्यक्ति

बल्कि उनकी वैचारिक गहराई, सामाजिक प्रतिबद्धता और अभिव्यक्ति की सादगी के कारण प्राप्त हुई है। वे उन साहित्यकारों में हैं जिन्होंने लघुकथा को न तो हल्की विधा समझा और न ही उसे मात्र मनोरंजन का माध्यम बनाया, बल्कि उसे समाज-परिवर्तन की सशक्त साहित्यिक विधा के रूप में प्रतिष्ठित करने का गंभीर प्रयास किया। सतीश राठी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी भाषा है। वे अत्यंत सरल, सहज और संप्रेषणीय शब्दावली का प्रयोग करते हैं, किंतु उस सरलता में विचारों की गहनता और संवेदनाओं की तीव्रता समाहित रहती है। उनकी रचनाएँ पढ़ते समय पाठक को भाषा की जटिलता से जुड़ना नहीं पड़ता, बल्कि वह सीधे कथ्य के मर्म तक पहुँच जाता है। यही कारण है कि उनकी लघुकथाएँ व्यापक पाठक-वर्ग तक सहजता से पहुँचती हैं और दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ती हैं।

सतीश राठी का पहला लघुकथा संग्रह 'शब्द साक्षी हैं' वर्ष 2002 में सत्य प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित होकर आया था। यह संग्रह काफ़ी चर्चित रहा था। इस लघुकथा संग्रह की भूमिका डॉ. सतीश दुबे ने लिखी थी। डॉ. सतीश दुबे ने अपनी भूमिका में लिखा था 'लेखकीय उद्देश्य की तमाम शक्तों के बहुत नजदीक होने के कारण सतीश राठी का नाम श्रेष्ठ लघुकथाकारों के बीच स्वतः दर्ज हो जाता है। लघुकथा के गुणात्मक एवं मात्रात्मक लेखन के साथ विधा के विकास हेतु किये गए प्रयासों की चर्चा जब कभी होगी, तब सतीश राठी नाम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा, यह तय है।' इस



संग्रह में छोटी-बड़ी 80 लघुकथाएँ हैं। 'दंभे-बंभे' लघुकथा अत्यंत संक्षेप में प्रभावी व्यंग्य प्रस्तुत करती है। इसमें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बीच सत्ता-संरक्षण की विडम्बना को चतुर्हाई से उजागर किया गया है। साधारण संवाद के माध्यम से सामाजिक असमानता पर तीखा कटाक्ष किया गया है, जो इसकी सबसे बड़ी सफलता है। 'भिखमो' लघुकथा बहुत कम शब्दों में एक गहरी विडम्बना प्रस्तुत करती है। इसमें दान देने की प्रक्रिया और उससे उजड़ी अव्यवस्था को प्रतीकात्मक रूप से दिखाया गया है, जहाँ सहायता का प्रयास ही हिंसक छीना-झपटी में बदल जाता है। अंत में दानकर्ता स्वयं भिखमंगा जैसा दिखने लगता है, जो सामाजिक असमानता और मानवीय विफलता पर तीखा व्यंग्य है। 'मिलावट' लघुकथा मिलावट और नैतिक पतन पर तीखा व्यंग्य प्रस्तुत करती है। सेठ स्वयं हर वस्तु में मिलावट करवाता है, लेकिन चाय में मिलावट का अनुभव होते ही उसका आक्रोश सामने आ जाता है। अंत में रामू की मुस्कानइत इस दोहरे चरित्र, दूसरों के साथ छल करने और अपने साथ होते ही उसे अस्वीकार करने को प्रभावी ढंग से उजागर करती है। 'सुअर' लघुकथा अत्यंत प्रभावशाली ढंग से मानवीय संवेदनशीलता और विरोधाभास को उजागर करती है।

भूखे बच्चे को भोजन देने से इनकार और उसी समय घर की झूठन को कचरे में डाल देना, समाज में व्याप्त असमान संवेदना और असंगत मूल्य-व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य है। अंत का प्रतीकात्मक 'सुअर' दृश्य इस विडम्बना को और अधिक कठोर बना देता है। सतीश राठी की लघुकथाएँ समकालीन हिंदी साहित्य में मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक यथार्थ की सूक्ष्म, किंतु सशक्त अभिव्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनकी रचनाओं का आधार मानव-मन की वे गहन अनुभूतियाँ हैं, जो प्रायः अदृश्य रहकर भी जीवन की आंतरिक धारा को संचालित करती हैं। सरल, सहज और अलंकरण-विहीन भाषा में रचित ये लघुकथाएँ कथ्य की तीव्रता और भाव-सघनता के कारण गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। प्रत्येक कथा पाठक को केवल घटनाओं से परिचित नहीं कराती, बल्कि उसे आत्ममंथन और सामाजिक यथार्थ के पुनर्पाठ के लिए प्रेरित करती है। इन रचनाओं में पारिवारिक संबंधों की ऊष्मा, नैतिक द्वंद्व, मूल्य-विचलन, करुणा और विडम्बना का मार्मिक चित्रण मिलता है। लेखक सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मानवीय व्यवहार की जटिलताओं को उक्रेते हैं, जिससे पाठक सहज ही कथा के भीतर प्रवेश कर स्वयं को उससे संबद्ध अनुभव करता है। सतीश राठी की दृष्टि यथार्थवादी होते हुए भी आशा से विमुक्त नहीं है; वे सामाजिक विसंगतियों के बीच सुधार और संवेदना की संभावना को निरंतर उजागर करते हैं। उनकी लघुकथाएँ व्यंग्य, करुणा और मौन प्रतिरोध के माध्यम से समय की विसंगतियों पर प्रभावी प्रहार करती हैं। समग्रतः, यह 'शब्द साक्षी हैं' संग्रह कथ्य, भाषा और संवेदन के संतुलन से युक्त होकर समकालीन हिंदी लघुकथा-साहित्य में एक उल्लेखनीय और स्थायी योगदान के रूप में स्थापित होता है।

## अफसरों-नेताओं की लड़ाई, केंद्र ने लिया नेताओं का पक्ष

### चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी, कहा- अधिकारियों को व्यवहार सिखाइए

भोपाल। मध्य प्रदेश में नेताओं और अफसरों के बीच टकराव की स्थिति है। विवाद केंद्र सरकार तक पहुंच गया। केंद्र सरकार के DoPT के डिप्टी सेक्रेटरी जीके रजनीश ने नेताओं के पक्ष में मुख्य सचिव अनुराग जैन को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा- अधिकारियों को सांसदों और विधायकों के साथ व्यवहार का तरीका सिखाइए। केंद्र ने कहा- अधिकारियों को तय प्रोटोकॉल का पालन हर हाल में करना होगा। सरकार ने चेतावनी दी है कि जनप्रतिनिधियों के पत्रों का समय पर और



विनम्र जवाब देना अनिवार्य है। बार-बार आ रही शिकायतों को केंद्र ने गंभीर संकेत मानते हुए राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) और संसद की ओर से पहले भी कई बार इस विषय पर दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। 12 जनवरी 2026 को भी एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था। मंत्रालयों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा गया था कि ये निर्देश जिला स्तर तक हर अधिकारी तक पहुंचाए जाएं, लेकिन इसके बावजूद स्थिति में खास सुधार नहीं दिखा, जिसके बाद केंद्र को दोबारा हस्तक्षेप करना पड़ा। DoPT ने 4 मई को चार महीने के भीतर दूसरी बार मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। इसमें सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के प्रति उनके व्यवहार और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करें। केंद्र ने यह भी पूछा है कि अब तक इन निर्देशों का पालन किस हद तक हुआ है।

### विधानसभा में बार-बार उठता है मुद्दा

मध्य प्रदेश विधानसभा में हर सत्र के दौरान विधायक यह मुद्दा उठाते हैं कि उन्हें प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता। उनके पत्रों का जवाब नहीं मिलता। हर बार सामान्य प्रशासन विभाग निर्देश जारी करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं दिखता। यही वजह है कि अब मामला केंद्र तक पहुंच गया है।

## थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों को चढ़ा दिया एचआईवी खून पांच महीने बाद जागी सरकार, ज्वॉइंट टास्क फोर्स का गठन

भोपाल। मध्य प्रदेश के सतना जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। थैलीसीमिया से जूझ रहे छह मासूम बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान एचआईवी संक्रमित खून चढ़ा दिया गया। हैरानी की बात यह है कि इस घटना के पांच महीने बीत जाने के बाद भी प्रशासन उस गुनहवार डोहर को नहीं ढूँढ पाया है, जिसकी एक लापरवाही ने इन बच्चों की जिंदगी दांव पर लगा दी। मामले की गंभीरता को



देखते हुए प्रदेश सरकार ने अब एक जॉइंट टास्क फोर्स का गठन किया है। सीएमएचओ डॉ. मनोज शुक्ला की अगुवाई वाली इस टीम में जिला अस्पताल, ब्लड बैंक, स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी और एफडीए के अफसरों को शामिल किया गया है। यह टीम न केवल डोहर की तलाश करेगी, बल्कि ब्लड बैंक के पूरे सिस्टम की खामियों को भी खंगालेगी।

### फर्जी नंबर और दलालों का जाल

जांच में अब तक जो सामने आया है, वो डराने वाला है। अधिकारियों के मुताबिक ब्लड बैंक के रजिस्टर में दर्ज आधे से ज्यादा डोहर का कोई अता-पता नहीं है। जो नंबर दिए गए थे, उनमें से कई गलत या बंद निकले। पिछले साल दिसंबर में हुए एक खुलासे में पता चला था कि ब्लड बैंक में बिचौलिया सक्रिय हैं, जो पैसों के लालच में किसी भी रिजल्टमेंट डोहर का खून बिना जांचे चढ़ा देते थे। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि सभी डोहर की पहचान कर उनका टेस्ट नहीं किया गया, तो यह एक बड़े हेल्थ क्राइसिस का रूप ले सकता है। नई टास्क फोर्स अब आर्थिक रिपोर्ट और टाइमलाइन की दोबारा जांच करेगी ताकि उन डोहर तक पहुंचा जा सके जिन्होंने सिस्टम की आंखों में धूल झांकी।

# भोपाल में चयनित शिक्षक-अभ्यर्थियों का प्रदर्शन

## 9 माह से नियुक्ति नहीं मिलने से नाराज, कहा-आदेश जारी नहीं हुए तो आंदोलन होगा

भोपाल। मध्यप्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी अब बड़ा मुद्दा बन गई है। माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों ने नियुक्ति न मिलने पर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। अभ्यर्थियों ने बुधवार को लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) के सामने प्रदर्शन किया और नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की। करीब 10,700 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी हुए लगभग 9 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक न तो नियुक्ति आदेश जारी हुए हैं और न ही चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू हो सकी है। अभ्यर्थियों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2022 में शुरू हुई थी। 2023 में पात्रता परीक्षा आयोजित की गई और अप्रैल 2025 में चयन परीक्षा ली गई। लंबी प्रक्रिया के बाद सितंबर 2025 में परिणाम घोषित किया और चयन सूची जारी हुई।

नियमों के बावजूद नहीं मिली नियुक्ति-अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका की धारा 3.28 के अनुसार चयन सूची जारी होने के तीन माह के भीतर नियुक्ति आदेश जारी करना अनिवार्य है। इसके बावजूद 8 से 9 महीने बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इससे अभ्यर्थियों में नाराजगी लगाता बढ़ती जा रही है। चयनित उम्मीदवारों का आरोप है कि अब तक न तो पात्र और अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है और न ही चॉइस फिलिंग कराई गई है। नवंबर 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक कई बार विभागीय अधिकारियों से संपर्क किया गया, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला। मार्च में चॉइस फिलिंग और अप्रैल में जॉइनिंग शुरू करने की बात कही गई थी, जो अब तक पूरी नहीं हुई।



### 10,700 युवाओं का भविष्य अधर में

लगभग 10,700 चयनित अभ्यर्थी इस देरी से प्रभावित हैं। उनका कहना है कि नया शैक्षणिक सत्र अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है, इसके बावजूद नियुक्ति न मिलना उनके भविष्य के साथ अन्याय है। अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पर किसी तरह का कोर्ट स्टै नहीं है, फिर भी देरी के लिए कानूनी कारण बताए जा रहे हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में शिक्षकों की भारी कमी है। करीब

1,895 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है, जबकि 29,116 स्कूलों में लगभग 99,682 शिक्षकों की कमी बताई गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और गंभीर है, जहां केवल 70 प्रतिशत पद ही भरे हुए हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों का सवाल है कि जब स्कूलों में इतनी कमी है, तो नियुक्ति में देरी क्यों की जा रही है। चयनित युवाओं की एक ही मांग है कि भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा कर नियुक्ति आदेश जारी किए जाएं। उनका कहना है कि लंबा इंतजार अब असहनीय हो गया है और यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो यह आंदोलन और तेज हो सकता है।

### मार्च-अप्रैल तक जॉइनिंग का आश्वासन दिया था

द्वंद्वर के दिनेश ठाकुर ने कहा कि कई अभ्यर्थियों की प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन जैसी सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन नियुक्ति अब भी लंबित है। उन्होंने कहा कि मार्च और अप्रैल तक जॉइनिंग का आश्वासन दिया गया था, लेकिन समय सीमा गुजरने के बाद भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। दिनेश के मुताबिक इन अभ्यर्थियों में कई किसान परिवारों से आते हैं, कुछ कोविंग पढ़ाकर अपना खर्च चला रहे हैं, तो कुछ छोटे-मोटे काम कर परिवार का सहारा बने हुए हैं। सभी का सपना सिर्फ एक सरकारी नौकरी हासिल करना है, लेकिन लंबा इंतजार अब मानसिक और आर्थिक दबाव में बदलता जा रहा है।

# आज से शुरू होगी एमपी बोर्ड द्वितीय परीक्षा

624 केंद्रों में 3.42 लाख विद्यार्थी, रहेगी सख्त निगरानी



भोपाल। मध्यप्रदेश में 10वीं और 12वीं के लाखों विद्यार्थियों के लिए एक और मौका आज से शुरू होने जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की द्वितीय बोर्ड परीक्षाएं 7 मई से आयोजित होंगी। परीक्षा को लेकर पूरे प्रदेश में तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं और प्रशासनिक स्तर पर सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। इस बार परीक्षा केवल आयोजन की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की भागीदारी को लेकर भी खास चर्चा में है, क्योंकि बड़ी संख्या में छात्रों ने इस अवसर से दूरी बनाई है।

### फेल ज्यादा, परीक्षा देने वाले कम

मुख्य बोर्ड परीक्षा में इस वर्ष कुल 4.89 लाख विद्यार्थी असफल हुए थे। इसके बाद उन्हें द्वितीय परीक्षा का मौका दिया गया, ताकि वे अपना एक साल बचा सकें। लेकिन आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं, वे चौंकाने वाले हैं। केवल 3.42 लाख विद्यार्थियों ने ही परीक्षा के लिए फार्म भरा है। इसका मतलब है कि करीब 70 प्रतिशत छात्र ही इस बार परीक्षा में शामिल होंगे, जबकि लगभग 30 प्रतिशत यानी करीब 1.47 लाख विद्यार्थियों ने यह मौका छोड़ दिया।

### 624 केंद्रों पर परीक्षा, राजधानी में 24

द्वितीय परीक्षा के आयोजन के लिए पूरे प्रदेश में 624 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। राजधानी भोपाल में लगभग 24 केंद्र निर्धारित किए गए हैं। हर जिले में केंद्रों का चयन इस तरह किया गया है कि अधिक से अधिक छात्रों को सुविधा मिल सके। संवेदनशील और अतिसंवेदनशील केंद्रों की पहचान कर वहां विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है। इन केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई है, ताकि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अव्यवस्था न हो।

समय और एंट्री के सख्त नियम- परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक तय किया गया है। विद्यार्थियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सुबह 8 बजे तक अपने-अपने परीक्षा केंद्रों पर अनिवार्य रूप से पहुंच जाएं, ताकि समय पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जा सके। प्रवेश को लेकर भी सख्ती बरती जा रही है।

परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले तक ही छात्रों को केंद्र में प्रवेश मिलेगा। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में एंट्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका उद्देश्य परीक्षा की अनुशासन व्यवस्था को बनाए रखना है।

सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम- परीक्षा की गोपनीयता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इस बार सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। प्रश्नपत्रों को पुलिस थानों में सुरक्षित रखा गया है और उन्हें तय प्रक्रिया के तहत केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष और प्रशासनिक प्रतिनिधियों की मौजूदगी में परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए ऑनलाइन सिस्टम भी लागू किया गया है, जिससे उच्च स्तर पर बैठकर भी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। नकल और अन्य गड़बड़ियों को रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्रॉड भी लगाता निरीक्षण करेंगे।

# कपास पर ड्यूटी खत्म करने की कोशिश में सरकार

### बुरहानपुर में सीएम डॉ. मोहन ने उद्योगपतियों के सामने किया ऐलान



उद्योगपति भी संघर्ष-चुनौतियों का सामना कर नई उड़ान भरते हैं। मेरा मानना है कि अब ये उड़ान और ऊंची जाएगी।

जन कल्याण के लिए कार्य कर रही है राज्य सरकार- उन्होंने कहा कि हमारे और आपके बीच कमिटमेंट है-व्यवहार है। उस व्यवहार पर हमें खरा उतरना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सरकार बनने के तीन महीने के अंदर जनता के जन-धन खाते खुलवाए। इससे उनका लोगों के पास सीधा धन

पहुंचाने का संकल्प पूरा हुआ। इससे पूरे देश की इकॉनोमी बदल गई। सभी को अपना हक मिला। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार दिन-रात जन कल्याण के लिए काम कर रही है। इसलिए हमने साल 2025 को उद्योग वर्ष और 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है।

विकास का द्वार है बुरहानपुर- सीएम ने कहा कि हमने कल ही कैबिनेट में व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन पास किया है। यह बोर्ड जिला स्तर तक

### कई वर्षों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे

छतरपुर के विवेक तिवारी ने बताया कि हजारों अभ्यर्थी पिछले कई वर्षों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि भर्ती में देरी के कारण कई उम्मीदवारों की पारिवारिक और आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। कुछ अभ्यर्थियों के माता-पिता इलाज के अभाव में परेशान हैं, तो कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके बुजुर्ग भती का इंतजार करते-करते दुनिया छोड़ गए। उन्होंने कहा कि कई उम्मीदवार अब 40 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं, जिससे उनके सामने भविष्य को लेकर गंभीर चिंता खड़ी हो गई है। विवेक के अनुसार नौकरी में लगातार देरी का असर युवाओं के व्यक्तिगत जीवन, विवाह और परिवार बसाने जैसे निर्णयों पर भी पड़ रहा है।

### दस्तावेज सत्यापन और अन्य प्रक्रियाएं पूरी हुईं

धीरेंद्र चौरसिया ने बताया कि वर्ष 2022 में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और अन्य प्रक्रियाएं पूरी होने के बावजूद अभी तक अंतिम नियुक्ति नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों ने कई बार भोपाल पहुंचकर धरना-प्रदर्शन किया। हर बार प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की ओर से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आया। धीरेंद्र का कहना है कि अभ्यर्थियों को कई बार लिखित और मौखिक भरोसा दिया गया कि जल्द पात्र-अपात्र सूची जारी होगी और जॉइनिंग प्रक्रिया पूरी होगी, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी पोर्टल पर कोई अपडेट नहीं है।

### राजा रघुवंशी हत्याकांड

## सोनम रघुवंशी को मिली बेल पर घमासान

### मेघालय सरकार ने अब हाईकोर्ट में दी चुनौती



भोपाल। मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपित सोनम रघुवंशी की जमानत को मेघालय सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। सरकार ने निचली अदालत का बेल आर्डर रद्द करने की मांग की है। मंगलवार को हाईकोर्ट ने सोनम को नोटिस जारी किया है। साथ ही अगले सप्ताह सुनवाई निर्धारित की है। उधर, सोनम को जमानत मिलने के बाद उसके कथित प्रेमी राज कुशवाह सहित चार अन्य आरोपितों ने भी जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर न्यायालय ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। मेघालय सरकार का कहना है कि ईस्ट खासी हिल्स की सेशन कोर्ट ने जमानत देते समय अपराध की गंभीरता और उसके न्यायिक प्रभावों पर पर्याप्त विचार नहीं किया। सोनम को उसकी गिरफ्तारी के कारणों की पूरी जानकारी थी, इससे जुड़े दस्तावेज भी अदालत में पेश किए। बता दें कि राजा रघुवंशी पत्नी सोनम के साथ हनीमून के लिए शिलांग गया था। जहां उसकी हत्या की हो गई। पुलिस ने सोनम, राज कुशवाह के अलावा विशाल चौहान, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत को भी गिरफ्तार किया था। 27 अप्रैल को न्यायमूर्ति डब्ल्यू. डिगंगडोह की कोर्ट ने गिरफ्तारी प्रक्रिया में खामियों का हवाला देते हुए सोनम को जमानत दी थी। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि सोनम को गिरफ्तारी के आधार की जानकारी ही नहीं दी गई।

### किसानों की आय बढ़ाना लक्ष्य

आएगा। इससे पहले हमने विकास समितियां भी बनाई थीं। भविष्य में हम निमाड इंवेस्टर्स समिट करेंगे। हमने व्यापारियों के लिए कई तरह के औचित्यहीन कानूनों को खत्म किया। बिजली को लेकर भी दो-तीन विभागों के बीच तालमेल चल रहा है। हम कपास पर लगने वाली ड्यूटी को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। व्यापारियों के लिए नया पहुंच मार्ग बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे दक्षिण का द्वार बुरहानपुर विकास का द्वार है। जिला भले ही छोटा, लेकिन लोग बड़े हैं।

### किसानों की आय बढ़ाना लक्ष्य

इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने कहा कि आज मैं बुरहानपुर के दौरे पर आया हूँ, बुरहानपुर में हमारी सरकार किसान कल्याण वर्ष के रूप में किसानों की आय बढ़ाने के साथ उद्योग और रोजगार पर भी महत्व दे रही है। हमारा प्रयास है कि उद्योग, व्यापार और व्यवसाय बढ़े जिससे प्रदेश और देश आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि हमारे दक्षिण में भाजपा के 200 से ज्यादा विधायक बने हैं, ऐसे में विधायकों के माध्यम से 9 मई को सरकार बनते आप और हम देखेंगे।